राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 13 फरवरी • 2024
www.rashtriyasahara.com

किसान बनाम सरकार

किसान 2020-21 की तरह इस बार फिर दिल्ली कूच कर रहे हैं। इसलिए इसे किसान आंदोलन का पार्ट दो कहा जा रहा है। राजधानी के आसपास के प्रदेशों के अलावा सूदूर मध्य प्रदेश के किसान भी लंबे समय तक राजधानी के घेराव की तैयारी के साथ आ रहे हैं। पिछले अनुभव फिर से न दोहराए जाएं इनके लिए सरकार और प्रशासन की तैयारी भी उसी तरह से है। किसानों को रोकने के लिए तमाम वैधानिक उपाय किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ, सरकार के मंत्री किसानों से वार्ता जारी रखे हुए हैं। सोमवार की शाम भी यह बातचीत चंडीगढ़ में हो रही है। इसके नतीजे पर देश की नजर रहेगी। सवाल है कि किसान क्यों बार-बार आंदोलन पर उतारू होते हैं? इसलिए कि उनकी जायज मांगें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। पहली मांग सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की है। इसके साथ 12 मांगें हैं। इनमें प्रमुख हैं-स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करने, किसानों और मजदूरों की संपूर्ण कर्जमाफी, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू करने, किसानों से लिखित सहमति लेकर चार गुना मुआवजा दिलाने, विश्व व्यापार संगठन से हटने और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर प्रतिबंध लगाने, किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन देने, बिजली संशोधन विधेयक 2020 रद्द करने, नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त जुर्माना लगाने और बीज की गुणवत्ता में सुधार करने, मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करना है। इनमें विश्व व्यापार मसला छोड़ दिया जाए तो ऐसी कोई मांग नहीं है, जिन्हें यह सरकार पूरी नहीं कर सकती है। हैट्रिक बनाने की मंसूबा रखने वाली नरेन्द्र मोदी सरकार से अपनी मांगें मनवाने का यह अच्छा मौका जान कर दिल्ली चलो का आह्वान किया गया है। इस समय सरकार को झुकाया जा सकता है। इसलिए सरकार रक्षात्मक मूड में रह सकती है और किसानों की कुछ मांगें मान सकती है। पर एक बैठक में कोई दीर्घकालिक समझौता नहीं होगा। मोदी सरकार की कार्यशैली के जानकारों का ऐसा मानना है। दूसरे, पिछले साल हुए हिंदी पट्टी के तीन राज्यों के किसानों का भाजपा के पक्ष में जम कर वोट करने का उदाहरण भी है। इसलिए सरकार किसानों के साथ ढिठाई कर सकती है, लेकिन इस बार रिस्क अधिक है। अगर उसने फिर से उन्हें थका देने की रणनीति रखेगी तो उसे घाटा हो सकता है। उसे किसानों की जायज मांगों पर विचार कर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए।

तेल की कीमतों पर रार

कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में फिर 80 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गईं। हालांकि भारतीय बाजार में राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल व डीजल की कीमतें अब भी स्थिर बनी हुई हैं। राज्यों के शहरों में मामूली परिवर्तन आ सकता है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल (यूके) 81.74 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि डब्ल्यूटीआई क्रूड (यूएस) 76.38 प्रति बैरल है। पिछले दिनों इनकी कीमतों में गिरावट आई थी। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96.72 प्रति लीटर है। डीजल 89.62 पर टिका है। मुंबई में 106.31 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है, डीजल 94.27 है। ध्यान रखें, राज्यों द्वारा लगने वाले टैक्स के कारण शहरों में पेट्रोल/डीजल के दामों में फर्क होता है। उम्मीद जताई जा रही थी कि फ्यूल उपभोक्ताओं को अगले कुछ दिनों में कीमतें गिरने की खबर मिल सकती है। बशर्ते तेल कंपनियों का मुनाफा बेहतर बना रहे। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का तेल वितरण कंपनियों को पेट्रोल/डीजल पर बेहतर मुनाफा मिल रहा है, लेकिन डीजल पर तीन रुपए प्रति लीटर के नुकसान के चलते इस मुनाफे में कमी आई। तीन तिमाही तक कंपनियों ने 69 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। कुछ समय पहले तक तेल कंपनियों ने पेट्रोल पर 11 रुपए प्रति लीटर तो डीजल पर 6 रुपए का मुनाफा कमाया है। हालांकि प्रति सिलेंडर गैस पर उन्हें 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि उसने पिछले कुछ समय से उपभोक्ताओं पर तेल की कीमतों का भार बढ़ने नहीं दिया है, परंतु लोगों का मानना है कि एक बार कीमतें बढ़ाने के बाद उन्हें नीचे लाने में कोताही की जाती है। क्रूड ऑयल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरने की खबरों पर उपभोक्ताओं की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, वे दाम गिरने का इंतजार करते हैं। आर्थिक समझ न रखने वाला आम आदमी भी कीमतों के उछाल व महंगाई के गणित को भली-भांति समझता है। वोट वह सरकार को देता है, कंपनियों को नहीं इसलिए सरकार को कंपनियों की नकेल कसनी जरूरी है। पेट्रोल/डीजल की कीमतों के बढ़ते ही माल ढुलाई, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, परिवहन समेत तमाम चीजों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। जो लोग वाहन नहीं रखते हैं, वे भी अपरोक्ष में इस महंगाई का हिस्सा बनते हैं इसलिए तेल की कीमतों को लेकर वे चिंतित ही नहीं रहते बल्कि उम्मीद रखते हैं कि कीमतों में कमी आ सके।

टू दि प्वाइंट/ आलोक पुराणिक

हम आपके हैं कौन

बाजार सब जगह है, वहां भी, जहां यह दिखाई नहीं देता। भिखारी, गैंगस्टर और बड़े कारोबारी इलाके बांट लेते हैं।

पॉलिटिक्स के बाजार में इलाके बंटे हुए हैं वहां के इलाके के बास वह, यहां के इलाके के बास वह। अपने इलाके में दूसरे को कोई पसंद नहीं करता। राहुल गांधी ममता बनर्जी के इलाके में घुसे, बंगाल में, यह ममता बनर्जी को मंजूर को नहीं है। मेरे बाजार में तुम्हारा क्या काम है। सबकी आफत यही है कि दूसरे के बाजार में एंट्री चाहिए और अपने बाजार में किसी को ना घुसने देना है। कस्टमर गिने चुने हैं, कस्टमर अगर दूसरे दुकानदार के पास चले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यह खतरा ही सबको खाए जाता है। इसके लिए पुरानी दोस्ती भी भुला दी जाती है। कुछ समय पहले ममता बनर्जी और राहुल गांधी एक फोटो में दिखते थे, अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम आपके हैं कौन।

कांग्रेस की हालत इस वक्त कमजोर दुकानदार जैसी है, दूसरे सारे दुकानदार उसे आंखें दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं हैं। कांग्रेस की हालत उस पुराने जमींदार जैसी दिखाई पड़ रही है, जिसके पुराने कारिंदे भी अब उन्हे आंखें दिखा रहे हैं। वक्त वक्त की बात है। हमेशा जीतने वाला सिकंदर कोई ना होता, वक्त से बड़ा सिकंदर कोई ना होता। सबको अपनी दुकान बचानी है।

उद्धव ठाकरे की शिवसेना की कह रही है कि हमें 23 सीटें चाहिए महाराष्ट्र में, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी को भी अपनी दुकान बचानी है। सबको अपनी दुकान बचानी और बढ़ानी है, कम पर कोई राजी ना हो रहा है। दुकान का सवाल जब आ जाता है, तो फिर विचारधारा वगैरह की बात भुला दी जाती है। बाजार दुकान ये सब असली आइटम हैं, विचारधारा तो हवाई बात है जी। नीतीश कुमार जिनसे लड़ने की बात कर रहे थे, उन्हीं के साथ आ कर मिल गए, जब उन्हें पता चला कि उनकी अपनी दुकान खतरे में है। दुकान बच जाएगी, तो बाकी बाद में सब बचा लेंगे। कौन कहां जा रहा है, यह बात इलेक्शन के बाद तक पता नहीं लगने वाली। कोई किसी का दोस्त नहीं, दुकान ही अपनी सबसे बड़ी दोस्त है।

अनमोल वचन

इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है

-अज्ञात

सियासी बवंडर का सच

हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी

अवधेश कुमार

झारखंड में चंपई सोरेन विश्वास मत प्राप्त कर चुके हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पहले और मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण तक और उसके बाद जिस तरह के राजनीति हुई उसका गहराई से विश्लेषण किया जाना जरूरी है। पद पर रहते हुए प्रवर्तन निदेशालय या ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं।

चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण के बावजूद विधायकों को हैदराबाद ले जाने का अर्थ क्या था? हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए और उन्हें इसका आभास भी था। बावजूद त्यागपत्र देकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इसका मतलब उनकी पार्टी और गठबंधन में ही द्वंद्व था। उनकी गिरफ्तारी आसानी से हुई भी नहीं। स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए उन्होंने वीडियो भी जारी किया। गिरफ्तारी के पहले के इस वीडियो संदेश में उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उन्हें पता है कि ज्यादा समय नहीं मिलेगा। सच यह है कि उन्होंने ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए जितना संभव था वह सब किया। दिल्ली स्थित अपने घर की तलाशी के मामले को उन्होंने अनुसूचित जाति-जनजाति कानून के तहत रांची में ईडी टीम के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कर दिया। उस मुकदमे में आरोप लगाया गया कि परेशान करने और छवि खराब करने के लिए तलाशी हुई थी। आखिर रांची और दिल्ली स्थित उनके घर की छापामारी में अनुसूचित जाति-जनजाति कानून कहां से आ गया? ईडी की मानें तो उन्होंने गिरफ्तारी टालने का प्रयास किया और गिरफ्तारी मेमो पर भी हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था।

उन्होंने ईडी के सम्मन के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की, जिसमें कहा कि एजेंसी जांच में मदन मदद न करने के आरोप में गिरफ्तार कर रही है जबकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि इस आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ईडी का कहना है कि उन्हें 8:30 बजे रात्रि में गिरफ्तारी मेमो दिया गया, लेकिन उन्होंने राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपने के बाद ही मेमो पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शक्ति के आधार पर स्वयं को बचाने का पूरा प्रयास किया। हेमंत की गिरफ्तारी रांची जमीन घोटाला मामले में हुई है। इसमें ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए 10 सम्मन भेजे। सातवीं बार सम्मन भेजते समय ईडी ने लिखा कि या तो आप पूछताछ के लिए आएं या हम आपके पास पहुंचेंगे। उसके बाद आठवें सम्मन में हेमंत ने ईडी को पूछताछ के लिए समय दिया था। 20 जनवरी को ईडी ने उनसे 7 घंटे तक पूछताछ की। उसके बाद 31 जनवरी को उनसे दोबारा पूछताछ हुई। 29 जनवरी को उनके दिल्ली और झारखंड आवास तथा झारखंड भवन में छापेमारी की गई पर हेमंत कहीं नहीं मिले। ईडी ने उनके घर से एक बीएमडब्ल्यू कार तथा 36 लाख नगद बरामद कर ले जाने की बात कही है। इसके पूर्व साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में भी ईडी ने हेमंत से 17 नवम्बर 2022 को 9 घंटे की पूछताछ की थी। इसमें उनसे उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा था। राजद और कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इसे जानबूझकर राजनीतिक प्रतिशोध के लिए बनाया गया फर्जी मामला बता रहे हैं। हेमंत दोषी हैं या नहीं यह तो न्यायालय के फैसले से तय होगा किंतु अभी तक की जांच और सामने आए तथ्य बहुत बड़े भ्रष्टाचार के प्रमाण देते हैं।

ध्यान रखिए, रांची में सेना के उपयोग करने लायक 4.55 एकड़ जमीन की गैरकानूनी तरीके से खरीद-बिक्री के मामले में दर्ज प्राथमिक से यह जांच शुरू हुई थी। इस मामले को हाथ में लेने के बाद ही ईडी ने जांच आगे बढ़ाई। ईडी ने जिस मामले पर सख्ती की वह रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में स्थित अत्यंत महंगी भूमि से संबंधित है। आरोप है कि खरीद-बिक्री में अवैध तरीके इस्तेमाल हुए और दस्तावेजों में हेराफेरी की गई। जांच में पाया गया है कि रांची सहित झारखंड में अनेक जगह भू माफियाओं का एक बड़ा तंत्र काम कर रहा है जो नेताओं, सरकारी अधिकारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों की मिलीभगत से दस्तावेजों में फेरबदल कर अवैध तरीके से भूमि बेच रहा है। इनमें वह जमीन भी शामिल है जिनकी खरीद-बिक्री कानूनन नहीं हो सकती। ईडी ने हेमंत की गिरफ्तारी के पहले 41 स्थानों पर छापामारी और पांच जगह पर सर्वे किया। छापेमारी में भू राजस्व विभाग के जाल मोहरे, जाली भू दस्तावेज, धोखेबाजों के बीच अपराध की कमाई के बंटवारे के प्रमाण, धोखाधड़ी करने से संबंधित तस्वीरें तथा अधिकारियों को रिश्वत देने के प्रमाण आदि जुटाए गए। जो नेता स्वयं भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हैं या जेल जा चुके हैं वह सब सोरेन के साथ खड़े हैं।

निस्संदेह, भारतीय जांच एजेंसियां अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करती रही हैं और सरकारी विरोधियों के विरुद्ध इनका इस्तेमाल भी। किंतु मामले के तथ्य जानने के बाद यह निष्कर्ष नहीं निकलता की हेमंत सोरेन पूरी तरह पाक साफ हैं और उनकी गिरफ्तारी झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमजोर कर सत्ता पाने के लिए की गई है। राजनीतिक संकट केवल इस कारण पैदा हुआ क्योंकि हेमंत सोरेन अंत अंत तक मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। झारखंड राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के साथ ही सरकारों के असमय अंत के लिए कुख्यात है इसलिए भय पैदा हो रहा था कि किसी अन्य के हाथों नेतृत्व सौंपने पर सरकार गिर सकती है। भाजपा के अधिकृत प्रवक्ता स्पष्ट कह रहे थे कि उन्हें जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है और उनके पास सरकार बनाने का अंक गणित नहीं है। भाजपा ने सरकार बनाने का दावा भी नहीं किया। पूरा संकट आपकी अपनी भूमिका से हुआ। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों पर पूरी तरह विश्वास होता कि ये नहीं टूटेंगे तो शपथ ग्रहण के बावजूद इन्हें हैदराबाद ले जाने के आवश्यकता पैदा ही नहीं होती। हेमंत सोरेन पर न्यायालय अंतिम फैसला क्या देता है इसे अभी परे रखते है।

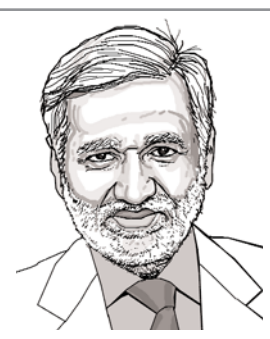

यह भारतीय राजनीति की त्रासदी है कि जिनने जनजातियों के साथ अन्याय, उनका उत्पीड़न, शोषण दमन की आवाज उठाकर आंदोलन किया, अलग झारखंड के लिए लड़ाइयां लड़ी, उनमें से अनेक या उनके वंशज, रिश्तेदार जहां मौका मिला सत्ता और प्रभाव का इस्तेमाल कर जितना संभव हुआ खुले हाथों से लूटा। जो लोग सोरेन को निर्दोष बता रहे हैं उनमें से ज्यादातर भ्रष्टाचार के आरोपी हैं और वह सब झारखंड की आम जनता के साथ धोखा करने वालों के पक्ष में खड़े हैं।

हेमंत सोरेन पर न्यायालय अंतिम फैसला क्या देता है इसे अभी परे रखते है। यह भारतीय राजनीति की त्रासदी है कि जिनने जनजातियों के साथ अन्याय, उनका उत्पीड़न, शोषण दमन की आवाज उठाकर आंदोलन किया, अलग झारखंड के लिए लड़ाइयां लड़ी, उनमें से अनेक या उनके वंशज, रिश्तेदार जहां मौका मिला सत्ता और प्रभाव का इस्तेमाल कर जितना संभव हुआ खुले हाथों से लूटा

लक्षद्वीप का ‘नारियल गुड़’ खासा महंगा खाद्य पदार्थ

- लक्षद्वीप का खास व्यंजन नारियल गुड़ बेहद लजीज और स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसका उपयोग 'लक्षद्वीप हलवा' और अन्य मिठाइयां बनाने में भी किया जाता है
- तीस लीटर नारियल रस को पकाकर गाढ़ा करने पर मात्र ढाई किलो गुड़ मिलता है, इसलिए यह महंगा है। इसकी कीमत एक हजार रुपए प्रति किलो है
- मांग ज्यादा होने से इसकी बिक्री ऑर्डर बुक करके की जाती है। मधुमेह के मरीज भी इसे खा सकते हैं। यह गुड़ लंबे समय तक खराब नहीं होता

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

यदि कांग्रेस पार्टी वास्तव में राष्ट्रीय जाति जनगणना के अपने वादे के प्रति गंभीर है, तो उसे तेलंगाना में सत्ता संभाल रही कांग्रेस सरकार को बिहार की तरह तेलंगाना में भी सर्वजातीय सर्वेक्षण कराने का निर्देश देना चाहिए।

उर्मिलेश, पत्रकार
@UrmileshJ

छठा खिताब पाने की रह गई कसक

अंडर-19 | मनोज चतुर्वेदी

आईसीसी टूर्नामेंटों में भारत की किस्मत एक बार फिर दगा दे गई। भारत को अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 79 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से क्रिकेट पर ऑस्ट्रेलियाई दबदबे पर एक बार फिर मुहर लग गई। भारत पिछले कुछ समय में ऑस्ट्रेलिया के हाथों विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और आईसीसी विश्व कप में हार चुका है और अब यह एक और हार दर्ज हो गई है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया इस चैंपियनशिप में चौथा खिताब जीतकर भारतीय दबदबे को चुनौती देने के करीब आ गया है। भारत ने अब तक इस चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा पांच खिताब जीते हैं।

पिछले साल के आखिर में भारतीय टीम आईसीसी विश्व कप में दबदबे वाला प्रदर्शन करके फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। उससे पहले उसे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। लगभग इसी तरह की स्थिति का भारत को इस अंडर-19 विश्व कप में सामना करना पड़ा। आस्ट्रेलिया के हैरी डिक्सन (42), वेबगेन (48) और हरजस सिंह (55) के सहयोग से 253 रन बनाने से वह ड्राइवर सीट पर बैठ गई थी। इस लक्ष्य को पाने के लिए भारतीय टीम सही मायनों में गंभीरता से प्रयास करती कभी नजर ही नहीं आई। यह सही है कि भारत को शुरुआत में ही चार झटके लग जाने पर उसकी स्थिति कमजोर नजर आने लगी थी, लेकिन आदर्श सिंह और पी मोलिया के खेलते समय तक हालात सामान्य होने लगे थे। आदर्श और मोलिया धीरे-धीरे विकेट पर जमने का प्रयास कर रहे थे और इस जोड़ी के जब पैर विकेट पर जमते दिखने लगे; तब ही मोलिया ने एंडरसन की एक गेंद पर छक्का लगाने का प्रयास करके विकेट खो दिया और भारत की स्थिति कमजोर कर दी। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय बल्लेबाजों ने यदि विकेट पर जमकर खेलने का प्रयास किया होता तो लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था कि इसे पाया नहीं जा सकता था। भारतीय बल्लेबाजों के गलत शॉट सलेक्शन ने भी स्थिति कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय कप्तान उदय सहारन ने भी माना कि विकेट पर ज्यादा समय बिताने में असफल रहने और खराब शॉट खेलने की वजह से हम खिताब जीतने में असफल रहे। भारतीय कप्तान इस चैंपियनशिप में अच्छे फैसलों वाली छवि बनाने में जरूर

कामयाब हुए। पर फाइनल में उनके कुछ फैसलों को टीम पर दवाब बनाने वाला माना जा सकता है। नमन तिवारी भारतीय टीम के प्रमुख पेस गेंदबाज हैं। पर उन्हें कप्तान उदय सहारन ने पहले ओवर में पिटने पर हटा दिया। यही नहीं उनके लगाए स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर कोई प्रभाव छोड़ने में कामयब नहीं हो सके। कप्तान ने नमन को जब याद किया, तब तक टीम शुरुआत में लगे पहले झटके से पूरी तरह उभर चुकी थी। सही मायनों में भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दवाब बनाने में असफल रहे। यह सही है कि सहारन अपना नाम भारत के लिए विजेता बनने वाले कप्तानों मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, उन्मुक्त चंद और पृथ्वी शॉ के साथ अपना नाम शुमार नहीं करा सके। पर इस चैंपियनशिप से भारत को कुछ भविष्य के सितारे जरूर मिल गए हैं। इनमें सचिन धास, खुद कप्तान उदय सहारन, मुशीर खान, लिम्बानी, उदय तिवारी और सौम्य पांडे के नाम लिए जा सकते हैं। सभी जानते हैं कि अंडर-19 विश्व कप किसी भी क्रिकेटर के लिए आगे बढ़ने में पहली सीढ़ी का काम करती है। पर इसमें चमक बिखेरने वाली प्रतिभाओं को राष्ट्रीय टीम में स्थान बनाने में दो-तीन साल लग जाते हैं। पर इस विश्व कप से यह जरूर पता चल जाता है कि अब किन खिलाड़ियों पर फोकस किया जाए। सहारन, धास और खान तीनों ऐसे बल्लेबाज हैं, जिनमें भविष्य के स्टार की झलक दिखती है। सहारन तो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 397 रन बनाने वाले रहे। इसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। सहारन की सबसे बड़ी खूबर लंगर डालकर खेलने की क्षमता होना है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम को संकट से निकालने की जरूरत थी, वह विकेट पर डटे रहे और इसमें उन्हें सचिन धास को भरपूर सहयोग मिला है।

सहारन ने सबसे ज्यादा रन जरूर बनाए पर वह खेले गए सातों मैचों में से किसी में भी प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बने। इसकी वजह उनका हमेशा सहायक की भूमिका में रहना है। वह सचिन धास का तो नाम ही तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। उनके लगाए शॉट तेंदुलकर की याद दिला देते हैं। इसी तरह मुशीर अपने भाई सरफराज की तरह ही प्रतिभाशाली हैं। वह दो शतकों और एक अर्धशतक से 360 रन बनाकर दूसरे स्थान पर रहे। बल्लेबाजों की तरह ही पेस गेंदबाज राज लिम्बानी और नमन तिवारी के साथ स्पिनर सौम्य पांडे में काबिलियत है कि वे सही मौका मिलने पर आने वाले वर्षों में टीम इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं। लिम्बानी की सबसे बड़ी खूबी विकेट से उछाल लेने और गेंद को तेजी से अंदर लाने की हैं। वहीं अभी से जडेजा कहे जाने वाले स्पिनर सौम्य पांडे इस चैंपियनशिप में भारत के लिए सबसे ज्यादा 18 विकेट लेने वाले हैं। जरूरत इन सभी प्रतिभाओं को अच्छे से मांजने की है।

बुद्धि | ओशो

मुल्ला नसरुद्दीन अपने मित्र के साथ सिनेमा देखने गया हुआ था। सिनेमा में सभी बोर हो रहे थे। पिक्चर जो थी, वह उनकी समझ के बाहर थी। मुल्ला नसरुद्दीन से कुछ ही आगे एक गंजा व्यक्ति बैठा हुआ था। मुल्ला के मित्र ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, पिक्चर तो बोर कर रही है; कुछ करो कि मनोरंजन हो। यदि तुम उस गंजे व्यक्ति के सिर पर एक चपत रसीद कर दो तो मैं तुम्हें दस रुपए दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि वह व्यक्ति नाराज न हो, क्रोधित न हो। मुल्ला बोला, अरे, यह कौन सी बात है, अभी लो! फिल्म का इंटरवल हुआ, मुल्ला उठा और पीछे से जाकर उसने गंजे आदमी की चांद पर एक चपत रसीद की और बोलाः अरे चंदूलाल, तुम यहां बैठे हो! हम तुम्हें देखने तुम्हारे घर गए थे। वह व्यक्ति बोलाः माफ कीजिए, भाई साहब, मैं चंदूलाल नहीं। आपको शायद गलतफहमी हुई है, मेरा नाम नटवरलाल है। मुल्ला ने कहा, ओह, क्षमा करिए, मुझे धोखा हो गया। और उसके बाद मुल्ला गर्व से छाती फुलाए मित्र के पास आया और बोला कि चलो, निकालो दस रुपए! मित्र ने दस रुपए दिए और बोला, मुल्ला, अब की बार बीस रुपए दूंगा यदि तुम इस गंजे आदमी की चांद पर एक चपत और लगा दो। मुल्ला बोला, अभी लो! मुल्ला गया और जाकर फिर उसकी चांद पर एक चपत रसीद की और बोलाः अबे साले, चंदूलाल, मुझे ही बेवकूफ बना रहे हो! मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तेरी यह नाटक करने की आदत जाएगी या नहीं? वह व्यक्ति फिर बोला, भाई साहब, माफ करिए, मैं चंदूलाल नहीं, नटवरलाल हूं। मैं किसी चंदूलाल को जानता भी नहीं! मुल्ला ने पुनः उससे क्षमा मांगी और वापस आकर मित्र से बीस रुपए वसूल किए। मित्र ने बीस रुपए देते हुए कहा, मुल्ला, यदि एक चपत तुम और लगा सको उस गंजे को तो ये पचास रुपए तुम्हारे! मगर शर्त वही है कि वह क्रोधित न हो। मुल्ला ने कहा, चिंता मत करो, होने दो पिक्चर समाप्त, चलो बाहर, अभी लगाए देता हूं एक चपत और। पिक्चर समाप्त हुई, सब बाहर आए, मुल्ला ने जाकर और भी जोर से उसकी गंजी खोपड़ी पर एक चपत रसीद की और बोला, अबे साले चंदूलाल के बच्चे, तुम साले यहां हो और तुम्हारे धोखे में भीतर हाल में मैंने बेचारे नटवरलाल को दो चपत रसीद कर दीं! उस व्यक्ति ने रुआंसे स्वर में उत्तर दिया, भाई साहब, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं; मैं चंदूलाल नहीं, नटवरलाल हूं।

रीडर्स मेल

जैविक खेती को मिले बढ़ावा

हाल के वर्षों में फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग अंधाधुंध तरीके से बढ़ा है। ज्यादा समझ और इसके हानिकारक परिणामों से अनजान किसान इसके इस्तेमाल में रत्ती भर भी नहीं हिचक रहे हैं। स्वाभाविक है इससे लोगों में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होने लगी हैं। लोग बीमार रहने लगे हैं और गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। अगर समय रहते रासायनिक खादों की जगह जैविक खादों का प्रयोग फिर से शुरू नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब हरी-भरी सब्जियां, फल और अनाज भी सेहत के दुश्मन बन जाएंगे, जिसका इलाज असंभव हो जाएगा। जैविक खाद का प्रयोग बढ़े इसके लिए सरकारों को किसानों के लिए विशेष योजनाओं की सौगात देनी होगी। किसानों को इस कार्य के लिए तकनीकी और आर्थिक सहायता देनी होगी। किसानों को पशुपालन के लिए जागरूक करने के लिए भी सरकारों को कुछ नीतियां बनानी चाहिए, ताकि किसान जैविक खाद तैयार कर सकें। हमने पहले भी देखा है कि इसके दुष्परिणाम कितने घातक रहे हैं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

सम्मान और राजनीति

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 23 जनवरी से 9 फरवरी के बीच सिर्फ 18 दिनों में पांच अहम शख्सियात को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देना उनका एक और चौंकाने वाले फैसला तो है ही, इसे लोक सभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कहना गलत न होगा कि आम चुनाव के मद्देनजर इन सम्मानों के जरिए गांव, किसान, बिहार, पचिमी उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण भारत के तेलंगाना व तमिलनाडु की राजनीति को साधने का प्रयास किया गया है। चयनित विभूतियों का गांवों की तरक्की, देश को आर्थिक संकट से उबारने और खाद्य पदार्थों के उत्पादन समेत कई अन्य क्षेत्रों में अतुल्य योगदान है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का अधिकार भले ही केंद्रीय सरकार का हो, लेकिन इस पर सियासत होना स्वभाविक है। मोदी सरकार ने पांच हस्तियों को भारत रत्न देकर अटल बिहारी वाजपेयी का रिकार्ड पीछे छोड़ दिया।

एमए कंवल जाफरी, बिजनौर, उप्र

प्रेम की भावना से ही होगी तरक्की

भोगवादी संस्कृति में पल रहा युवा भावों की गहराई को समझ ही नहीं पाता। प्रेम के लिए इस तरह की सोच कितनी सही और कितनी गलत है, इसका फैसला भी खुद युवाओं को ही करना होगा। हम अक्सर देखते हैं कि भारत में प्रेम युगल को हीन भावना से देखा जाता है। प्रेम या प्रणय को हमेशा टैबू या वर्जना बनाकर पेश किया गया है। एक समाज या समुदाय तब अच्छी तरह से कार्य करता है जब उनमें एकजुटता और प्रेम की भावना होती है। जिस समाज में हर कोई एक-दूसरे से नफरत करता हो और दूसरों का विकास न देख पाता हो, वह कभी तरक्की नहीं कर सकता। अतः किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि लोग एक-दूसरे से प्रेम करें। प्रेम विभिन्न जाति, नस्ल, लिंग, समुदाय, धर्म, क्षेत्र आदि के लोगों को एकता के सूत्र में बांधेगा। प्रेम सभी भावनाओं में सबसे गहरा और सबसे सार्थक है।

नृपेंद्र अभिषेक नृप, ई मेल से
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 182
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

मेहनत और शिक्षा के बल पर हम मजबूत अर्थव्यवस्था और सबके लिए अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। - जूलिया गिलार्ड

कतर में कथित जासूसी के आरोप में आठ भारतीय पूर्व नौसैनिकों को मिली मौत की सजा को बमुश्किल डेढ़ महीने पहले उम्रकैद में तब्दील कराने और अब इन सैनिकों की रिहाई कराने में विदेश मंत्रालय ने जो भूमिका निभाई है, उसकी सराहना तो होनी ही चाहिए, यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत भी है।

बड़ी कूटनीतिक जीत

कतर में कथित जासूसी के आरोप में आठ भारतीय पूर्व नौसैनिकों को मिली मौत की सजा को बमुश्किल डेढ़ महीने पहले उम्रकैद में तब्दील कराने और अब इन सैनिकों की रिहाई कराने में भारत के विदेश मंत्रालय ने जो भूमिका निभाई है, उसकी सराहना तो होनी ही चाहिए, यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। तब तो और भी, जब शुरुआत में कतर ने इस मामले में काफी सख्त रुख दिखाया था, जबकि नौसेना में काम कर चुके ये लोग न केवल काबिल हैं, बल्कि कतर ने इनके कथित जुर्म के बारे में भी ज्यादा खुलासा नहीं किया था। उल्लेखनीय है कि ये पूर्व नौसैनिक कतर की नौसेना को प्रशिक्षण देने वाली एक निजी कंपनी में काम करते थे और भारतीय दूतावास को पहली बार सितंबर, 2022 में इनकी गिरफ्तारी का पता चला। नौसैनिकों के परिवार जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले, तब भारत ने कतर को मनाने के लिए तुर्किये और अमेरिका तक की मदद ली। भारत को पहली कूटनीतिक कामयाबी तब मिली, जब पिछले वर्ष दिसंबर में कतर की अपीलीय अदालत ने पूर्व सैनिकों की सजा घटाकर इन्हें और इनके परिजनों को राहत दी थी। तब फैसले का स्वागत करते हुए सरकार ने कहा था कि विस्तृत फैसला आने पर अगला कदम उठाने पर विचार किया जाएगा। इससे पहले कॉप-28 के दौरान भी भारतीय प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर से मिलकर वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के हाल-चाल जाने थे। उन्होंने बेशक इन गिरफ्तार पूर्व नौसैनिकों का उल्लेख नहीं किया, लेकिन यह उनका प्रभाव ही था, जिसकी वजह से कतर के रुख में उसके बाद से ही नरमी दिखने लगी थी। कतर की ओर से भारतीय पूर्व नौसैनिकों की रिहाई का फैसला जिस वक्त लिया गया है, वह भी बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच फिलहाल रिश्ते नई ऊंचाई को छू रहे हैं और हाल ही में दोनों देशों के मध्य 78 अरब डॉलर का एक गैस समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत 2048 तक कतर से तरल

प्राकृतिक गैस (एलएनजी) खरीदेगा। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से कतर भारत के लिए उपयोगी है। इसके अलावा, इस वक्त कतर में करीब आठ लाख भारतीय कामगार और छह हजार से ज्यादा भारतीय कंपनियां भी काम कर रही हैं। ऐसे में, कतर द्वारा पूर्व भारतीय नौसैनिकों को छोड़ने के फैसले से दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई गर्माहट उम्मीद है कि दोनों को भविष्य में और अधिक नजदीक लाएगी।

मजबूत होती अर्थव्यवस्था

यह लगातार छठी बार है, जब रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास के मद्देनजर जीडीपी विकास का पूर्वानुमान उच्च स्तर पर रखा गया है। अनुमान लगाया गया कि मुद्रास्फीति लगातार कम होगी और वित्त वर्ष 2025 में औसत मुद्रास्फीति दर 4.5 फीसदी रहेगी।

बीते दिनों छह से आठ फरवरी के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की वित्तीय वर्ष 2024 की आखिरी बैठक संपन्न हुई, जिसके नतीजे काफी हद तक उम्मीदों के मुताबिक रहे। लेकिन सरकारी बॉन्डों का रिटर्न (लाभ) बढ़ गया और इसकी घोषणा होते ही शेयर बाजार में मामूली गिरावट देखने को मिली। जब एमपीसी का रुख काफी हद तक अपेक्षा के अनुकूल ही था, तो शेयर बाजारों में यह निराशा क्यों?

इस बैठक में एमपीसी ने सभी दरों को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने का फैसला किया। यह लगातार छठी बार है, जब रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास के मद्देनजर जीडीपी विकास का पूर्वानुमान उच्च स्तर पर रखा गया है। संसद में पेश अंतरिम केंद्रीय बजट के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखने की भी सराहना की गई। अनुमान लगाया गया कि मुद्रास्फीति लगातार कम होगी और वित्त वर्ष 2025 में औसत मुद्रास्फीति दर 4.5 फीसदी रहेगी।

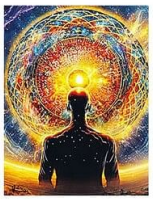

अजय बग्गा
शेयर बाजार विशेषज्ञ

लेकिन चार कारणों से नीतिगत घोषणा अनुमान से अधिक कठोर रही। पहला, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने के लिए अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति पर अंकुश लगाया जाएगा। फरवरी, 2023 से फरवरी, 2024 के शुरू तक पिछले 12 महीनों में रिजर्व बैंक ने तरलता पांच लाख करोड़ रुपये के बड़े दैनिक अधिशेष से घटाकर 1.1 लाख करोड़ रुपये के दैनिक घाटे में ला दिया है। बाजार इस तरलता घाटे को रिजर्व बैंक द्वारा पहले की गई दरों में बढ़ोतरी के तेजी से हस्तांतरण के रूप में देखता है।

वास्तव में, पिछले 12 महीनों में ऋण दरों में औसतन 19 आधार अंकों की वृद्धि हुई है, जबकि जमा दरों में 80 आधार अंकों की तेज वृद्धि हुई है। चूंकि बैंकों के लिए जमा वृद्धि की तुलना में ऋण वृद्धि तेजी से बढ़ी है, इसलिए रिजर्व बैंक ने असुरक्षित खुदरा ऋण वृद्धि को कम करने के

लिए और अधिक उपायों की घोषणा की है।

ऐसे में, उम्मीद यह थी कि रिजर्व बैंक तरलता बढ़ाने वाले कुछ उपायों की घोषणा करेगा और बैंकों की तरलता बढ़ाने के लिए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) पर भी कुछ राहत देगा। लेकिन ऐसे किसी उपाय की घोषणा तो नहीं ही की गई, नीतिगत रुख को भी तटस्थ स्तर पर नहीं रखा गया। यह दूसरा कारण था, जिसने बाजार को अस्थिर किया।

तीसरा बिंदु अपेक्षित था, फिर भी इसने बॉन्ड और शेयर बाजारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक इस सूचना को बार-बार प्रसारित करने के प्रति सतर्क रहे हैं कि वे ब्याज दरों में कटौती बाद में और बाजार की अपेक्षा से धीमी गति से करने के बारे में सोचेंगे। भारत में भी बाजार को उम्मीद थी कि अप्रैल से जून में रिजर्व बैंक दरों में कटौती करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने स्पष्ट किया कि मुद्रास्फीति के जोखिम अब भी संतुलित हैं, खासकर लाल सागर के व्यवधान और तेल की कीमतों के प्रभाव को देखते हुए। बाजार में इसे कठोर रुख के रूप में देखा गया और दर में कटौती की उम्मीदें आगे चली गईं। नतीजतन बॉन्ड पर रिटर्न बढ़ गया और बैंकों के शेयर में मामूली गिरावट देखी गई।

चौथा बिंदु उपभोक्ताओं के समर्थन में उठाए गए कदम को लेकर था, जिसके तहत रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए ऋण ग्राहकों की खातिर सभी शुल्कों को एक ब्याज दर गणना में शामिल करना अनिवार्य कर दिया। हम देखते हैं कि बैंक ऋण के लिए आकर्षक ब्याज दर की घोषणा करते हैं, मसलन वे 8.4 फीसदी ब्याज दर की घोषणा करते हैं, और फिर उसमें प्रोसेसिंग फीस, डाक्यूमेंटेशन फीस, अग्रिम ईएमआई और न जाने क्या-क्या जोड़ देते हैं। इतने सारे शुल्कों के कारण ग्राहकों को यह पता ही नहीं चल पाता कि उनके ऋण की वास्तविक लागत क्या है। इसलिए रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए सर्व-समावेशी ऋण दर घोषित करना अनिवार्य कर दिया है। इससे बैंकों के लाभ पर असर पड़ सकता है, खासकर निजी बैंकों को, जो ऐसे बहुत से शुल्क वसूलते हैं।

अगले तीन महीनों में बैंकिंग प्रणाली 1.5 से 2.5 लाख करोड़ रुपये के घाटे में रह सकती है, बशर्ते रिजर्व बैंक तरलता बढ़ाने के लिए कोई उपाय नहीं कर देता। तरलता की आपूर्ति में कमी ने नीतिगत हस्तांतरण में तेजी ला दी है, लेकिन कम तरलता और बैंक ऋण पर सख्ती के साथ यह चिंता भी है कि ऋण वृद्धि में मौजूदा मजबूती कायम नहीं रह सकती है। यह बैंकों के लिए आत्म-सुधार तंत्र के रूप में कार्य कर सकता है और हम तरलता पर अधिक संतुलित रुख देख सकते हैं: बहुत सख्त नहीं, लेकिन बहुत ढीला भी नहीं।

अनुमान है कि जुलाई में जब वित्त वर्ष 2025 के लिए पूर्ण केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, तब रिजर्व बैंक सबसे पहले तरलता को ज्यादा संतुलित स्तर पर ले जाएगा। फिर यह अपने नीतिगत रुख को वर्तमान प्रतिबंधात्मक स्तर से बदलकर तटस्थ कर देगा। और तीसरे चरण में वास्तविक दर में कटौती शुरू हो जाएगी। इस मामले में बहुत कुछ अमेरिकी फेड, यूरोप के ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड के रुख पर निर्भर करेगा। उम्मीद है कि जून-जुलाई में ये सब केंद्रीय बैंक दरों में कटौती शुरू कर देंगे। इसलिए रिजर्व बैंक भी अगस्त या अक्तूबर में पहली बार दर में कटौती करेगा।

रिजर्व बैंक के पिछले रिकॉर्ड के विश्लेषण से पता चलता है कि यह आम तौर पर अपना नीतिगत रुख बदलने में सुस्त रहा है, जो दरों की तुलना में ब्याज दरों से काफी निकटता से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बार जब ब्याज दरों में कटौती शुरू हो जाएगी, तो उम्मीद है कि एमपीसी की चार बैठकों में 100 आधार अंकों या ब्याज दर में एक प्रति की कटौती होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत है कि यह रिजर्व बैंक को कटौती की सुविधा देगी।

जाहिर है, बैंकों में ऋण वृद्धि धीमी हो जाएगी, जमा दरें कम से कम जून-जुलाई तक ऊंची रहेंगी और लाभ में कमी आएगी, क्योंकि धन की लागत ऋण शुल्क से अधिक बढ़ जाएगी। ऐसे में बैंकों का प्रदर्शन खराब हो सकता है। जहां तक बॉन्ड रिटर्न की बात है, जुलाई, 2024 तक धीरे-धीरे इसमें गिरावट आएगी और उसके बाद तेज गिरावट आएगी, क्योंकि बॉन्ड बाजार रिजर्व बैंक द्वारा दर में कटौती की उम्मीद करेगा और इसी उम्मीद में रिटर्न घटा देगा।

फिलहाल एमपीसी ने इन सबको स्थगित रखा है, जिसे रिजर्व बैंक के कठोर रुख के रूप में देखा जा रहा है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

खलील जिब्रान

जिस प्रकार से नदी मैदानी इलाके की ओर तेजी से बहती है और वहां पहुंचने पर उसकी गति धीमी हो जाती है, उसी प्रकार सुख का आविर्भाव जिस उल्लास से होता है, सुख पाने के बाद वह उल्लास स्थायी नहीं रहता।

मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा में ही सुख पाता है

थोड़े ही लोग ऐसे हैं, जो अपने जीवन से पूर्ण संतुष्ट और सर्वथा चिंतामुक्त हैं। मनुष्यों में जो देवत्व है, उसका विकास स्वतंत्र रूप से होना चाहिए तथा शैतानियत को दफन कर देना ही पुण्य है। मृत्यु शरीर का नाश करती है, परंतु उसकी सुकृति तथा अपकृति का नाश करने में वह सक्षम नहीं है। गतिशील चक्र के सदृश हम लोग समय के द्वारा अनुशासित हैं।

जीवन अशांत निद्रा है। उस निद्रा का स्वप्न अभिलाषा द्वारा पोषित है। धर्म अच्छी तरह जोती गई खेती के समान है, जिसमें स्वर्ग के आकांक्षी अथवा नर्क-ज्वाला से आतंकित व्यक्ति के मनोरथ की रोपनी तथा सिंचाई हुई है। परंतु ये सब पुनर्जीवन की गणना के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। श्रेष्ठतम नियति की उपलब्धि के अतिरिक्त उन लोगों ने न देवपूजन ही किया और न पश्चाताप ही किया। उनके दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय में धर्म ने भी एक व्यापार का रूप ले लिया है।

क्या न्याय और मानव निर्मित कानून मुझे हंसने और रोने के लिए बाध्य नहीं करता है? दीन और दुर्बल अपराधी दंडित होता है, परंतु धनी और समर्थ अपराधी को यश और मान मिलता है और वह सर्वथा दोषमुक्त रहता है, क्योंकि उसके अपराध धन-दौलत और वंशानुगत यश के आवरण में छिपे रहते हैं। फूल की चोरी करने वाले व्यक्ति को नीच समझा जाता है, परंतु भूमि पर जबरन अधिकार करनेवाले को वीर की संज्ञा दी जाती है। शरीर के हत्यारे को प्राणदंड मिलता है, परंतु 'आत्मा' की हत्या करनेवाला व्यक्ति स्वतंत्र होकर विचरण करता है। आत्मा की ऊर्जा केवल शक्तियों की क्षमता है। समय पर यह ऊर्जा सभी विरोधी तत्वों को चूर-चूर कर देती है। इन्हें दोषी मत ठहराओ, बल्कि इनकी अनिष्ठा, अज्ञानता, अयोग्यता तथा दुर्बलता पर दया दिखाओ। श्रेष्ठतम ज्ञान स्वप्न है, जिसे विजेता स्थिर होकर धारण करता है और जो उपहास्य द्वारा संत्रास नहीं पाता, बल्कि शांतिपूर्ण विस्तार में गतिशील होता है। नागरिकों की भीड़ में घृणित और विनीत, दोनों हैं।

सुख एक कल्पित वस्तु है, जिसकी तलाश हम लोग करते हैं। अगर वह सुख प्राप्त होगा, तो निश्चित रूप से थका देनेवाला होगा। जिस प्रकार से नदी मैदानी इलाके की ओर द्रुतगति से बहती है और वहां पहुंचने पर उसकी गति धीमी और शांत हो जाती है, उसी प्रकार सुख का आविर्भाव जिस उल्लास से होता है, सुख की प्राति के बाद वह उल्लास स्थायी नहीं रहता, उसकी गति मंद हो जाती है। मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा में ही सुख पाता है। जब वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, तब उसका जोश ठंडा हो जाता है और फिर दूर-देशांतर-गमन के लिए वह उत्कंठित होता है। क्या तुम ऐसे सुखी व्यक्ति से मिलना चाहोगे, जो अपनी नियति से संतुष्ट है और जनसाधारण से पृथक होकर शांतिपूर्ण निर्वाण की आराधना करता है? आत्मा अविनाशी है। वह हमेशा समृद्धिशाली और विकसित होगी। जिस प्रकार उत्तरी वायु के संचार से पृथ्वी पुष्पों से आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार दक्षिण वायु उसके सौंदर्य का प्रत्यर्पण करती है।

अविनाशी है आत्मा...

सूत्र

अपने जीवन से संतुष्ट रहने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन लोगों की अच्छाइयों को जरूर याद रखना चाहिए। सुख की इच्छा कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार सुख यदि हासिल हो जाता है, तो उसके प्रति वह उत्साह नहीं रहता, जो पहले हुआ करता था। लेकिन आत्मा अविनाशी है, जो हमेशा विकसित होती रहेगी।

दूसरा पहलू

करीब 72 करोड़ साल पहले पृथ्वी की आर्द्र जलवायु और नीला पानी एक ठंडी और बंजर दुनिया में बदल गया था।

जब पृथ्वी एक बर्फ का गोला थी

करीब 72 करोड़ साल पहले, पृथ्वी की आर्द्र जलवायु और लहराता नीला पानी एक ठंडी और बंजर दुनिया में बदल गया था। भूवैज्ञानिक इतिहास के इस चरण को वैज्ञानिकों ने नाम दिया 'स्नोबॉल अर्थ।' यानी बहत्तर करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी जमी हुई बर्फ का एक गोला थी। लेकिन ऐसी क्या वजहें थीं, जिनके चलते हमारी पृथ्वी बर्फ का गोला बन गई और फिर करीब छह करोड़ साल तक वैसी ही बनी रही, यह एक रहस्य है।

सिडनी यूनिवर्सिटी की एक टीम ने पिछले हफ्ते यह खुलासा किया कि उन्होंने यह रहस्य ढूंढ निकाला है। इस टीम का मानना है कि बहत्तर करोड़ साल पहले दरअसल ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों में काफी कमी आ गई थी, जिससे पूरे ग्रह पर कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन भी बेहद कम हो गया था और यही पृथ्वी के हिमाच्छादन की वजह बना। दरअसल, कम कार्बन डाई ऑक्साइड पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोक कर रखना मुश्किल बना देती है। शोध टीम का यह निष्कर्ष भी है कि अगर यह कमी ज्यादा होती, तो पृथ्वी ग्रह अब तक के सबसे लंबे हिम युग में जा सकता था। सिडनी यूनिवर्सिटी की भूविज्ञानी एड्रियाना ड्यूटकिविक्ज कहती हैं, 'आज निस्संदेह मनुष्य पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, पर करोड़ों साल पहले जब ग्रह पर कोई नहीं था, तब हर चीज भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही निर्धारित होती थी।'

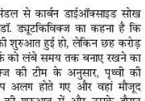

कैटरीना मिलर

सिडनी यूनिवर्सिटी की टीम ने खुलासा किया कि ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों में कमी से कॉर्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम हो गया और यही पृथ्वी के हिमाच्छादन की वजह बना।

एक लोकप्रिय विचार यह है कि आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से निकलने वाले खनिजों ने वायुमंडल से कार्बन डाईऑक्साइड सोख लिया, जिससे गहरी ठंडक पैदा हुई।

पृथ्वी के बर्फ के गोले में तब्दील होने पर कई तरह से विचार किया जा चुका है। एक लोकप्रिय विचार यह है कि आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से निकलने वाले खनिजों ने वायुमंडल से कार्बन डाईऑक्साइड सोख लिया, जिससे गहरी ठंडक पैदा हुई। लेकिन डॉ. ड्यूटकिविक्ज का कहना है कि मुमकिन है कि इससे पृथ्वी के बर्फ में बदलने की शुरुआत हुई हो, लेकिन छह करोड़ साल तक बर्फ यों ही जमी नहीं रह सकती। बर्फ को लंबे समय तक बनाए रखने का कोई तो रहस्य जरूर होगा। डॉ. ड्यूटकिविक्ज की टीम के अनुसार, पृथ्वी की खिसकती टेक्टॉनिक प्लेटों के कारण महाद्वीप अलग होते गए और वहां मौजूद ज्वालामुखी भी। इसके बाद टीम ने हिमयुग की शुरुआत में और उसके दौरान ज्वालामुखीय गैसों के उत्सर्जन की मात्रा की गणना की और इस आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले। हालांकि डॉ. ड्यूटकिविक्ज खुद मानते हैं कि भूविज्ञान में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता।

©The New York Times 2024

आंकड़े

देश में गोशाला

हमारे देश में गायों की देखभाल के लिए विभिन्न राज्यों में 7,676 पंजीकृत गोशालाएं हैं, जिनमें सर्वाधिक राजस्थान में हैं।

राजस्थान	2,269
गुजरात	1,418
मध्य प्रदेश	905
हरियाणा	640
उत्तर प्रदेश	582

स्रोत : Animal Husbandry Department

याज्ञवल्क्य ने कहा, 'आत्मा की ज्योति सर्वोपरि है। हमारी आत्मा सदैव सच्चा रास्ता दिखाने को तत्पर रहती है। आत्मा जैसी अनूठी ज्योति किसी और तत्व में नहीं है।'

सच्ची ज्योति

अंतर्यात्रा
शिवकुमार गोयल

महर्षि याज्ञवल्क्य और मिथिला नरेश जनक एक दिन बैठकर सत्संग कर रहे थे। जनक जी ने जिज्ञासा व्यक्त की, 'महर्षि, हम किसकी ज्योति से देखने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं?'

महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 'सूर्य की ज्योति से।' जनक जी ने पूछा, 'जब सूर्य अस्त हो जाता है, तो हमें प्रकाश कहां से प्राप्त होता है?' उत्तर मिला, 'चंद्रमा से।'

उन्होंने फिर पूछा, 'अमावस्या की घनी रात में यदि हम वन में भटक जाएं, तो कौन प्रकाश का काम देता है?'

महर्षि ने कहा, 'तब शब्दों द्वारा हमारा रास्ता प्रकाशमान होता है। दूर खड़ा दूसरा व्यक्ति कहता है कि भटको नहीं, मेरी आवाज को माध्यम बनाकर इधर आ जाओ।' और लोग उसी आवाज पर आगे बढ़ते हैं। अब जनक जी ने अंतिम प्रश्न किया, 'महर्षि यदि सूर्य, चंद्रमा तथा शब्दों का भी अभाव हो, तो आखिर हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रकाश का रूप कौन लेता है?'

महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 'आत्मा की ज्योति सर्वोपरि है। जनक जी, हमारी आत्मा सदैव हमें सच्चा मार्ग दिखाने को तत्पर रहती है। आत्मा जैसी अनूठी ज्योति किसी और तत्व में नहीं है।' महर्षि की बातों से जनक जी की जिज्ञासा का समाधान हो गया।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 5 अप्रैल, 1955

चूहे खा जाते हैं हर साल 78 लाख टन अनाज

भारतीय चूहे

प्रतिवर्ष ७८ लाख टन गल्ला खा जाते हैं

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रामेश्वर लाल ने भारत सरकार की एक रिपोर्ट से मनोरंजक सूचना दी है, जिसमें कहा गया कि देश में 80 करोड़ चूहे हैं, जो औसतन करीब डेढ़ छटांक की दर से हर साल 78 लाख टन अनाज खा जाते हैं।

रील्स के बढ़ते ट्रेंड के दौर में तस्वीरें

भले ही रील्स लोकप्रिय हो रही हैं, पर ऐसा नहीं है कि वे पूरी तरह स्थिर तस्वीरों को समाप्त कर देंगी। दोनों प्रारूपों की अपनी-अपनी ताकत है।

मुकुल श्रीवास्तव

समाज

इंटरनेट के आने से पहले की दुनिया में बदलाव की गति धीमी थी। पर अब यह प्रक्रिया इतनी तेज है कि नया द्रुत गति से पुराना हो रहा है। सोशल मीडिया के आने के बाद लोगों ने अपनी बात कहने के लिए ब्लॉग पोस्ट और तस्वीरों को जरिया बनाया, फिर वीडियो और ऑडियो सामग्री की धूम मची, पर तस्वीरें या फोटोग्राफ मांग में लगातार बने रहे। ये तस्वीरों का ही कमाल था, जिसने मोबाइल से अपनी खुद की तस्वीरें लेने की कला 'सेल्फी' को विकसित किया और देखते-देखते सारी दुनिया में छा गई। लेकिन इंटरनेट पर रील्स की बढ़ती लोकप्रियता ने इन तस्वीरों की लोकप्रियता खत्म तो नहीं की, पर कम जरूर कर दी है।

रील्स जैसा ही एक और प्रारूप इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रहा है, वह है 'व्लॉगिंग'। ये दो अलग-अलग डिजिटल मीडिया प्रारूप हैं, जिनका उपयोग वीडियो बनाने और साझा करने के लिए किया जाता है, जिनके कारण तस्वीरों की लोकप्रियता में कमी आ रही है। व्लॉगिंग का मतलब होता है कि व्यक्तिगत अनुभवों, ज्ञान, कला, साहित्य, यात्राओं आदि को वीडियो के माध्यम से साझा करना। इनकी अवधि रील के मुकाबले ज्यादा होती है।

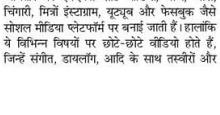

रील्स एक प्रकार की वीडियो सामग्री है, जो आमतौर पर एमएक्स शॉर्ट वीडियो, मौज, जोश, चिंगारी, मित्रों इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनाई जाती हैं। हालांकि ये विभिन्न विषयों पर छोटे-छोटे वीडियो होते हैं, जिन्हें संगीत, डायलॉग, आदि के साथ तस्वीरों और क्लिप्स मिलाकर बनाया जाता है। रील में गति होती है, जबकि तस्वीरों में अगर गति लानी भी है, तो रील्स का ही सहारा लेना पड़ेगा।

सोशल इनसाइडर के अनुसार, रील्स इंस्टाग्राम पर किसी भी अन्य सामग्री से दोगुनी पहुंच उत्पन्न करती हैं। रील्स की औसत पहुंच दर 30.81 फीसदी है, जबकि कैरोसल (ऐसी पोस्ट, जिसमें एक से अधिक फोटो या वीडियो हों, जिन्हें उपयोगकर्ता फोन ऐप के माध्यम से पोस्ट पर स्वाइप करके देख सकते हैं।) और फोटो पोस्ट की औसत पहुंच दर क्रमशः 14.45 फीसदी और 13.14 फीसदी है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2022 और 2023 के बीच कैरोसेल पोस्ट की पहुंच दर में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंस्टाग्राम रील्स की पहुंच दर उन खातों के लिए कहीं अधिक है, जो कम फॉलोअर्स रखते हैं, 500 फॉलोअर तक के खातों की औसत पहुंच दर 892 फीसदी होती है। हालांकि यह उन खातों की पहुंच दर से कई गुना ज्यादा है, जिनके पास ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, पर बड़े खातों वालों के इंस्टाग्राम रील्स की पहुंच में भी काफी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जा रही है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में फोटोग्राफ की तुलना में रील्स अधिक प्रभावी तरीका है, जिससे सुविधाजनक ढंग से जनसंचार और लोकप्रियता पाने में मदद मिल सकती है। डिमांड्सएज वेबसाइट के अनुसार, 23.025 करोड़ इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं के साथ भारत इंस्टाग्राम रील्स का सबसे बड़ा बाजार है, दूसरे नंबर पर अमेरिका (15.975 करोड़) और तीसरे स्थान पर ब्राजील (11.945 करोड़) है।

रील्स इसलिए ज्यादा लोकप्रिय हैं, क्योंकि वे स्थिर तस्वीरों की तुलना में अधिक आकर्षक होती हैं। रील्स कहानियां बता सकती हैं, गति दिखा सकती हैं, और संगीत और ध्वनि प्रभाव जोड़ सकती हैं, जो उन्हें अधिक आकर्षक और दिलचस्प बना सकता है। दूसरा, रील्स बनाना पहले से कहीं अधिक आसान है। स्मार्टफोन और वीडियो संपादन ऐप्स के आगमन के साथ कोई भी रील बना सकता है। तीसरा, रील व्यापक दर्शकों तक पहुंचने का एक शानदार तरीका है। उन्हें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शॉर्ट्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर साझा किया जा सकता है, जिनके अरबों उपयोगकर्ता हैं। फिर भी स्थिर चित्रों का महत्व खत्म नहीं हुआ है। उन्हें घरों और व्यवसायों में मुद्रित और प्रदर्शित किया जा सकता है और कई वर्षों तक संजोया भी जा सकता है। रील्स का उपयोग अक्सर हास्य, रचनात्मकता और व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए होता है।

इसलिए भले ही रील्स लोकप्रिय हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे पूरी तरह से स्थिर तस्वीरों को समाप्त कर देंगी। दोनों प्रारूपों की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं, और वे आने वाले वर्षों में सह-अस्तित्व के साथ कितने वक्त तक रह पाएंगी, यह बताना अभी मुश्किल है।

दैनिक जागरण

मनुष्य की इच्छा ही उसके दुख का मूल कारण है

शानदार कूटनीतिक जीत

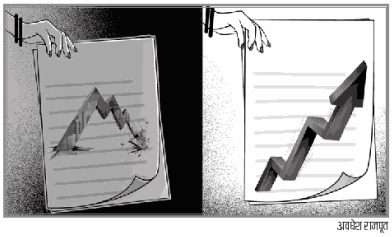

कतर की जेल में बंद आठ पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई और उनमें से सात का स्वदेश आ जाना एक ऐसी शुभ सूचना है, जिससे पूरे देश ने चैन की सांस ली है। इन भारतीयों की सकुशल रिहाई भारत की एक शानदार कूटनीतिक जीत है। यदि इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया जा रहा है तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले दुबई में कतर के शासक से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद ही पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा रद कर दी गई थी। इसके बाद जब यह माना जा रहा था कि मौत की सजा से बच गए इन भारतीयों को या तो कतर की जेल में लंबे समय तक रहना होगा या फिर उन्हें अपनी शेष सजा भारत आकर काटनी होगी, तब यह सुखद सूचना आई कि उन्हें रिहा कर दिया गया। यह बात तो शायद ही पूरी तौर पर सामने आए कि भारतीयों की रिहाई के लिए किस स्तर पर कैसे गहन कूटनीतिक प्रयास किए गए, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि अपारदर्शी न्यायिक व्यवस्था वाले कतर सरीखे देश से अपने नागरिकों को सकुशल वापस लाना एक कठिन काम था। इस कठिन काम को करके मोदी सरकार ने न केवल अपनी कूटनीतिक क्षमता का लोहा मनवाया, बल्कि इस संदेश को नए सिरे से रेखांकित भी किया कि भारतीय नागरिक विश्व में कहीं भी संकट में फंसे हों, उनकी सहायता के लिए कोई कसर शेष नहीं छोड़ी जाती। इसका प्रमाण तब भी मिला था, जब युद्धग्रस्त यमन और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सकुशल निकालकर लाया गया था।

कतर की कैद से आठ पूर्व भारतीय नौसैनिकों के मुक्त होने की खबर के साथ ही यह सूचना आई कि भारतीय प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के दो दिवसीय दौरे के बाद दोहा भी जाएंगे। इसका अर्थ है कि खाड़ी सहयोग परिषद के देशों एवं भारत के बीच आर्थिक-व्यापारिक संबंध और मजबूत होने वाले हैं। खाड़ी सहयोग परिषद के अधिकांश देशों और विशेष रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ओमान से भारत के संबंध पहले से ही मधुर हैं। इन मधुर संबंधों की ही एक बानगी है, अबूधाबी में मंदिर का निर्माण। प्रधानमंत्री इसी मंदिर का उद्घाटन करने वहां जा रहे हैं। यह भव्य मंदिर केवल संयुक्त अरब अमीरात और भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों का सूचक ही नहीं है, बल्कि इसका भी परिचायक है कि मोदी सरकार योग के बाद भारतीय संस्कृति के अन्य मूल्यों का भी प्रचार-प्रसार इस्लामी देशों में भी कर पाने में सक्षम है। इस सिलसिले को और गति दी जानी चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक ऐसी अनुपम संस्कृति है, जो विश्व को बंधुत्व और प्राणि मात्र के कल्याण का संदेश देती है। ऐसी संस्कृति का विस्तार मानवता के हित में है। भारतीय संस्कृति को विश्व के कोने-कोने में पहुंचाना इसलिए भी श्रेयस्कर है, क्योंकि इससे भारत की पहचान के साथ उसका कद भी बढ़ेगा।

जानलेवा लत

वीडियो और आनलाइन गेम्स को प्रतिबंधित करने के लाख प्रयासों के बावजूद युवाओं के मन-मष्तिष्क पर इसका बहुत ही मजबूत असर है। खासकर कम उम्र के बच्चों को इसकी लत लग जाए तो लंबे समय तक छूटती नहीं है। ऐसे दर्जनों उदाहरण सामने आ चुके हैं जहां इस लत के चक्कर में युवा जानलेवा कदम उठा लेते हैं। इससे हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। यह स्थिति परिवार, समाज और देश के लिए हानिकारक होती है। ऐसा ही एक मामला झारखंड के पाकुड़ के बागमुड़ा पत्थर खदान में देखने को मिला जहां मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलते-खेलते एक युवा ने खदान में कूदकर अपनी जान दे दी। आनलाइन मोबाइल गेम का उसके मस्तिष्क पर कितना असर था उसे इसी बात से समझा जा सकता है कि देर रात दो बजे वह मोबाइल पर गेम खेलते हुए ही वह मारो-मारो चिल्लाते हुए घर से निकला और नींद में ही खदान तक पहुंच गया। यहां वह खदान में कूद गया जिस कारण से मौत हो गई। हालांकि इसके पीछे की पूरी कहानी अभी अस्पष्ट है। उसके पिता ने पुलिस को यही जानकारी दी है कि वह मोबाइल पर गेम खेलने का लती था और लाख प्रयासों के बावजूद इसे छोड़ नहीं रहा था। इस तरह की घटनाएं झारखंड के कई जिलों में पहले भी हो चुकी हैं। मोबाइल पर गेम खेलने के लिए मना करने के कारण आत्महत्या करने की घटनाओं के साथ-साथ अभिभावकों से मारपीट करने जैसे सैकड़ों मामले झारखंड के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इतना होने के बावजूद भी घटनाओं में कमी होती नहीं दिख रही है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों का मन आनलाइन गेम्स में इतना नहीं उलझे कि वे मौत के मुहाने तक पहुंच जाएं।

> मोबाइल गेम की लत जिस तरह बच्चों, किशोरों एवं युवाओं को अपनी चपेट में ले रही है वह गंभीर चिंता का विषय है

भारत के आर्थिक उत्थान का दस्तावेज

विवेक देवराय

> श्वेत पत्र न केवल अतीत की गलतियों को दर्शाता है, बल्कि उन्हें सुधारने की दिशा में उठाए गए मौजूदा सरकार के प्रयासों को भी रेखांकित करता है

आदित्य सिन्हा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिनों लोकसभा में 'भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र' प्रस्तुत किया। श्वेत पत्र में भारत के आर्थिक परिदृश्य की गहन समीक्षा है। यह मुख्य रूप से वर्ष 2004 से 2014 के बीच केंद्र की सत्ता में रही संप्रग सरकार की आर्थिक नीतियों पर केंद्रित है। यह दौर ऐसी आर्थिक कुनीतियों का था, जिसमें अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। भ्रष्टाचार और वित्तीय अनुशासनहीनता चरम पर थी। परिणामस्वरूप भारत की गिनती 'फ्रैजाइल फाइव' में होने लगी। तब फ्रैजाइल फाइव विश्व की उन पांच नाजुक अर्थव्यवस्थाओं वाले ऐसे समूह के रूप में कुख्यात हो गया था, जिनकी आर्थिकी बदहाली की ओर बढ़ रही थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अक्सर उस दौर की नीतियों का स्मरण कराते रहते हैं और हाल में एक कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उस दौर में दिशाहीन आर्थिक नीतियों ने देश की आर्थिकी में निवेशकों का भरोसा घटा दिया था। चारों ओर अव्यवस्था, अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल था।

श्वेत पत्र में उन तीन प्रमुख चुनौतियों को चिह्नित किया है, जो मौजूदा सरकार को संप्रग शासन से विरासत में मिली थीं। पत्र में चर्चा है कि वर्तमान सरकार ने उन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए। पहला मुद्दा बैंकों में बढ़ रही गैर-निष्पादित आस्तियों यानी एनपीए का था। यह कोई छिपी बात नहीं कि संप्रग सरकार में राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अस्तित्व में आई 'फोन बैंकिंग' यानी सिफारिशों पर मिलने वाले कर्जों के कारण बैंकों का एनपीए निरंतर बढ़ता गया। सरकारी बैंकों की वित्तीय सेहत बहुत खराब हो गई थी। खास तौर से 2006 से 2008 के बीच उनके फंसे हुए कर्ज का मर्ज बढ़ने पर ही रहा। इस चुनौती से पार पाने के लिए मोदी सरकार ने 'फोर आर' यानी रिकग्निशन, रिजोल्यूशन, रीकैपिटलाइजेशन और रिफार्म्स का सहारा लिया। इस चहुंमुखी रणनीति से आशय था चुनौती की पहचान, उसके लिए संभावित समाधान, पुनर्पूंजीकरण और आवश्यक एवं अपेक्षित सुधार। इस रणनीति की परिणति पारदर्शी बैंकिंग प्रणाली और ऋणशोधन एवं दिवालिया संहिता यानी आइबीसी जैसी विधायी पहल के रूप में सामने आई, जिसके व्यापक स्तर पर सुफल प्राप्त हुए।

दूसरी चुनौती 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से उबरने के लिए अपनाई गई संप्रग सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के प्रभाव से निपटने की थी। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए संप्रग सरकार ने आवश्यकता एवं अर्थव्यवस्था की क्षमता से कहीं अधिक राजकोषीय प्रोत्साहन दिए। इसने सरकारी खजाने पर भारी दबाव बढ़ा दिया। राजकोषीय घाटा खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर लिया जा रहा कर्ज अपनी कहानी खुद कह रहा था। ऐसी बदरंग स्थिति को सुधारने के लिए राजग सरकार ने कर सुधारों और खर्च के ढांचे को दुरुस्त करने की दिशा में व्यापक पहल कीं। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का सूत्रपात भी इसी दौर में हुआ। यहां तक कि कोविड-19 जैसी आपदा के दौरान भी राजकोषीय अनुशासन को लेकर प्रतिबद्धता जारी रही।

बुनियादी ढांचे की अनदेखी और अनुत्पादक खर्चों की हिमायत आर्थिक मोर्चे पर संप्रग सरकार की तीसरी कमजोर कड़ी साबित हुई। संसाधनों की बंदरबांट में पूंजीगत व्यय के लिए आवंटन कम होता गया। इससे महंगाई से लेकर चालू खाते का घाटा बढ़ता गया तो मुद्रा अवमूल्यन की शिकार हो रही थी। इसके उलट राजग सरकार ने बुनियादी ढांचे और परिसंपत्ति सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूंजीगत व्यय में भारी बढ़ोतरी की। इसका आर्थिकी पर व्यापक चक्रीय प्रभाव देखने को मिला। संतुलित एवं समावेशी वृद्धि को सुनिश्चित करने में इस उत्पादक खर्च की अहम भूमिका रही। वित्त वर्ष 2014 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 के लिए पूंजीगत व्यय में चार गुना अधिक आवंटन हुआ। संप्रग सरकार के दौरान कुल व्यय में जहां पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत रही तो राजग सरकार में यह औसतन 14.5 प्रतिशत और गत पांच वर्षों में 15.8 प्रतिशत रही। इसका परिणाम यह हुआ कि 2014 से पहले खर्च की गुणवत्ता में जो कमी का सिलसिला बना हुआ था, वह रुझान पलटा। अब राजस्व व्यय भी कहीं अधिक रणनीतिक रूप से किया जा रहा है, जो राज्य की कल्याणकारी भूमिका का निर्वहन करने पर केंद्रित है।

अवधेश राजपूत

ठोस आर्थिक सुधारों की दिशा में शिथिलता के लिए भी संप्रग सरकार की आलोचना होती है। वह अतीत के सुधारों और अनुकूल वैश्विक परिस्थितियों के भरोसे ही रही। इस दौरान ऊंची मुद्रास्फीति और बेलगाम राजकोषीय घाटे ने आम लोगों के लिए जीवनयापन महंगा कर दिया। साथ ही भारत की दीर्घकालिक आर्थिक बुनियाद को मजबूत करने का अवसर भी गंवा दिया गया। इसके विपरीत मौजूदा सरकार पारदर्शी शासन को प्राथमिकता बनाए हुए है। नीति-निर्माण में जनसामान्य की भी सहभागिता हो रही है। श्रृंखलाबद्ध सुधारों के अतिरिक्त डिजिटलीकरण, बुनियादी ढांचा विस्तार और कारोबारी सुगमता के साथ ही सरकार आर्थिकी को नई ऊर्जा देने एवं सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के उपाय कर रही है। व्यय सुधार आयोग की स्थापना राजकोषीय कुशलता और राष्ट्र के विकास में राजकीय निधि के सदुपयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन प्रयासों से वृहद आर्थिक स्थायित्व की स्थिति निर्मित हुई है। आइएमएफ जैसी कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इसे सराहा है। इससे घरेलू एवं विदेशी निवेशकों का भरोसा बहाल हुआ है। समग्रता को समर्पित यह दृष्टिकोण शासन में गतिशीलता, भारत की आर्थिक संभावनाओं में प्रखरता और भविष्य की वृद्धि को लेकर आशावादिता को झलकाता है। कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र न केवल अतीत में की गई गलतियों को दर्शाता है, बल्कि उन्हें सुधारने की दिशा में उठाए गए मौजूदा सरकार के प्रयासों को भी रेखांकित करता है। ऐसे प्रयास भविष्य के दृष्टिकोण से अनुकरणीय हैं, जो आर्थिक नीतियों को लेकर जनता की समझ एवं उनकी सहभागिता बढ़ाने के साथ ही भविष्य की वृद्धि एवं समृद्धि की दृष्टि से उनके निहितार्थों को भी समझाते हैं।

(देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं)

response@jagran.com

माहौल बिगाड़ने वाले बयान

अवधेश कुमार

> कुछ मुस्लिम संगठनों और नेताओं के न्याय व्यवस्था के खिलाफ आपत्तिजनक बयान चिंतित करने वाले हैं

कुछ मुस्लिम संगठनों और नेताओं द्वारा ज्ञानवापी, अयोध्या और हल्द्वानी के बनभूलपुरा की हिंसा से लेकर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने पर दिए जा रहे वक्तव्य न केवल चिंताजनक, बल्कि खतरनाक भी हैं। पिछले दिनों वाराणसी की जिला अदालत में हिंदुओं को ज्ञानवापी के व्यास जी तलगृह में पूजा करने का अधिकार दिया। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष न्यायालय गया, जहां उसे सफलता नहीं मिली। जिला अदालत का आदेश नहीं आने तक किसी हिंदू ने वहां जबरदस्ती पूजा करने की कोशिश नहीं की। बावजूद इसके मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि ज्ञानवापी में जो हुआ, उससे मुस्लिमों के साथ अमनपसंद लोगों को धक्का पहुंचा है। इससे भी खतरनाक और आपत्तिजनक आरोप उनके द्वारा न्यायालय पर जल्दबाजी में निर्णय करने का लगाना है। उन्होंने कहा कि दूसरे को कहने का मौका नहीं दिया गया। वहीं जमीयत उलमा ए हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि आज भारत की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर बड़ा सवालिया निशान लग गया है। उनके चाचा मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मथुरा, ज्ञानवापी और बाबरी जैसे मामले उठते रहे, लेकिन अब जिस तरह से ये उठे हैं, उससे महसूस होता है कि कानून के आलोक में न्याय देने वाले कोर्ट में लचक और ढील पैदा हुई है, जिससे इबादतगाहों पर कब्जे में सहूलियत मिली है। मजहब आधारित मुकाबले में फैसला कानून के आधार पर नहीं हो रहा। यह स्थानीय कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दिख रहा है। तमाम कानूनी किताबों पर आग लगाओ। मुल्क इससे नहीं चलेगा।' ऐसे उकसावे भरे बयान माहौल बिगाड़ने वाले हैं।

ऐसे कुछ बयान बरेली के मौलाना तौकीर रजा और जूनागढ़ के मुफ्ती सलमान अजहरी की ओर से भी दिए गए हैं। अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय का अंतिम फैसला आने के बाद से ही एक वर्ग यह दुष्प्रचार करता आ रहा है कि न्यायालय ने माना था कि वहां मंदिर था ही नहीं। यह दुष्प्रचार इतना हुआ कि जगह-जगह यह बात सुनने को मिलती है। सैफुल्लाह रहमानी ने फिर इसे दोहराते हुए कहा है कि बाबरी मामले में भी कोर्ट ने माना कि मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं था, लेकिन आस्था को देखकर एक पक्ष में फैसला कर दिया गया। अयोध्या, मथुरा और ज्ञानवापी धर्मस्थलों के विवाद कई सौ वर्षों से चल रहे हैं। आस्था के आधार पर फैसला देना होता तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही न्यायालय ने बहुसंख्यकों के पक्ष में आदेश दे दिया होता। अयोध्या मामले में न्यायिक संघर्ष कितना लंबा चला, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। उच्चतम न्यायालय के आदेश को पढ़ने से आभास होता है कि सच को सच साबित करने के लिए हिंदुओं को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उच्चतम न्यायालय मुख्यतः पांच बातों पर आश्वस्त हुआ तभी आदेश सुनाया। एक, बाबरी ढांचे के नीचे हिंदू स्थल होने के पुरातात्विक प्रमाण मौजूद हैं। दो, बाबरी ढांचे के निर्माण में भी हिंदू धर्मस्थल की सामग्री का इस्तेमाल हुआ था। तीन, भारतीय धर्मशास्त्रों में भी श्रीराम के जन्म और उस स्थान को लेकर जगह-जगह विवरण मौजूद हैं। चार, कई विदेशी यात्रियों के साथ भारत के महापुरुषों की यात्राओं के विवरण में भी अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तक जाने की चर्चा है। और पांच, राम मंदिर के लिए संघर्ष के भी प्रमाण मौजूद हैं। फिर इसमें केवल आस्था कहां है?

जमीयत उलमा ए हिंद के मौलाना महमूद मदनी। प्रेट्र

ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार में कोई भी मंदिर के सारे अवशेष खुली आंखों से भी देख सकता है। संघर्षों के विवरण भी इतिहास के पन्नों में हैं। बावजूद इसके न्यायालय ने अभी तक ज्ञानवापी को मंदिर मानने का फैसला नहीं दिया है। इसके लिए हिंदुओं को न्यायालय में पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। व्यास जी तलगृह में 1993 तक पूजा होती थी। मुलायम सिंह यादव की सरकार ने बिना कानूनी आदेश के घेरेबंदी कर पूजा रुकवा दी थी। होती हुई पूजा रोक दी गई, लेकिन हिंदू समाज ने वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसी आज मुस्लिम संगठन और नेता दे रहे हैं। अब वहां पूजा के आदेश को पाने में भी 30 वर्ष से ज्यादा लग गए। बावजूद इसके कुछ मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि न्यायालय मस्जिदों पर कब्जे करवा रहा है। जबकि व्यास तलगृह में पूजा करने वाला परिवार मौजूद है, जिसकी वंशावली में लगभग 500 वर्षों से पूजा करने के विवरण हैं। कहां तो इन मुस्लिम संगठनों को न्यायालय के फैसले से सीख लेकर हिंदू समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए इतिहास में किए गए अपराधों का परिमार्जन करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वे धमकी दे रहे हैं। वे धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल उत्तराखंड सरकार की ओर से लागू की गई समान नागरिक संहिता को लेकर भी कर रहे हैं। हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर भी पुलिस पर हमला करने वालों का पक्ष लिया जा रहा है।

भड़काऊ बयान दे रहे मुस्लिम नेताओं के संपर्क भारत के बाहर के मुसलमानों से भी हैं। उनके ऐसे बयानों पर वे किस तरह की प्रतिक्रिया कर रहे होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। सरकार, किसी नेता, संगठन आदि के विरुद्ध बयानबाजी एक बात है, किंतु संपूर्ण भारत राष्ट्र, समाज और न्याय व्यवस्था को एक मजहब के विरुद्ध बताने का क्या मतलब लगाया जाए? ये पहले भी इस तरह के वक्तव्य देते रहे हैं। चूंकि पहले के वक्तव्यों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं हुई और न आम भारतीय उनके विरुद्ध उठकर खड़ा हुआ, इस कारण इनका हौसला बढ़ता गया। इन्हें रोकना अपरिहार्य हो गया है। कानूनी एजेंसियों के साथ समाज के हर वर्ग को इनके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। मुसलमानों में भी एक बड़ी आबादी इनसे सहमत नहीं है। उसे भी इनका हर स्तर पर प्रतिकार करते हुए समाज को इनसे सावधान करना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

निष्काम-सकाम कर्म

इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं-सकामी और निष्कामी। सकामी व्यक्ति पहले कामना करता है, फिर कर्म। बिना किसी कामना के वह कर्म नहीं करता। पहले वह लाभ देखता है, फिर कदम आगे बढ़ाता है। यदि कर्म में लाभ नहीं तो उसे नहीं करता। ऐसा व्यक्ति मन में लोभ रखता है, जबकि निष्कामी व्यक्ति बिना किसी कामना, आकांक्षा या लोभ के पूरे मन से कर्म करता है। इसी कर्म की महिमा का वर्णन गीता में है, क्योंकि ऐसा कर्म व्यक्ति को संसार के बंधन से मुक्त करता है।

जब व्यक्ति सकाम कर्म करता है तो उसकी दृष्टि हर पल लक्ष्य पर होती है। कर्म के माध्यम से वह उस लक्ष्य को पाना चाहता है। जिस तरह हम किसी पशु के गले में रस्सी बांधकर खींचते हैं, उसी तरह सकामी व्यक्ति के गले में भी कामनाओं की रस्सी स्वतः बंध जाती है। इसी सकामता के कारण वह मनुष्य की श्रेणी से गिरकर पशु की श्रेणी में आ जाता है। जिस तरह किसी पशु को भोजन दिखाए जाने पर वह स्वतः उस ओर चला जाता है, वही दशा सकामी व्यक्ति की होती है।

वहीं निष्कामी व्यक्ति के सामने लक्ष्य कामना नहीं, बल्कि भगवान होते हैं। वह हर कर्म भगवान तक पहुंचने के लिए करता है। उसके मन में यह लोभ कभी नहीं जागता कि कर्मों का यथेष्ट फल मिले। वह भगवान के लिए समर्पित भाव से कर्म करता है। इसलिए वह उच्च श्रेणी में आता है। उसे कभी कामना की रस्सी नहीं खींचती, कोई सांसारिक फल आकर्षित नहीं करता। उसके कर्मों से प्रसन्न होकर भगवान उसे पुरस्कृत करते रहते हैं। उसे इतना देते हैं, जितना सकामी व्यक्ति को कभी नहीं मिलता। सकामी व्यक्ति कभी तृप्त एवं संतुष्ट नहीं होता, जबकि निष्कामी व्यक्ति हर पल संतुष्ट रहता है। उसे जो मिलता है, भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करता है। वह उसी में सबसे ज्यादा प्रसन्न होता एवं आनंद मनाता है।

नीता देवी

सेक्सटार्शन के चंगुल में फंसते युवा

सोनम लववंशी

> सेक्सटार्शन यौन शोषण से जुड़ा भ्रष्टाचार का एक रूप है, जिसमें मांगें पूरी न होने पर व्यक्ति की अंतरंग जानकारियां लीक करने की धमकी दी जाती है

सेक्सटार्शन की दुनिया काफी खतरनाक हो चली है। सेक्सटार्शन यौन शोषण से जुड़ा भ्रष्टाचार का एक रूप है, जिसमें मांगें पूरी न होने पर किसी व्यक्ति की अंतरंग जानकारियां, यौन तस्वीरें या वीडियो आनलाइन शेयर या लीक करने की धमकी दी जाती है और उसकी आड़ में पैसा या यौन संबंध बनाने की मांग की जाती है। यह एक ऐसी समस्या है, जिससे निजात पाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सेक्सटार्शन से वर्तमान समय में युवा पीढ़ी काफी अधिक पीड़ित है, क्योंकि यह उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जब व्यक्ति भावनाओं में जल्दी बह जाता है और अक्सर आनलाइन ठग इसी का फायदा उठाकर अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। यौन शोषण का यह अपराध अब बड़े शहरों से निकलकर छोटे-छोटे शहरों तक पहुंच गया है। दरअसल पिछले कुछ समय से सेक्सटार्शन के जरिये लोगों को शिकार बनाने की घटनाएं बढ़ी हैं। पहले आनलाइन फ्राड करने वाट्सएप या मैसेंजर पर लोगों को वीडियो काल करते हैं। जैसे ही वे काल रिसीव करते हैं, सामने से कोई लड़की अश्लील हरकत करते या कपड़े उतारते हुए बात करना शुरू कर देती है। साथ ही इसका वीडियो भी रिकार्ड कर लेती है। इसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल।

अधिकतर मामलों में तो सामने वालों को पता भी नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब तक उन्हें इस बात की भनक लगती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अक्सर देखा गया है कि जागरूकता की कमी के चलते लोग सेक्सटार्शन के जरिये ठगी के शिकार हो जाते हैं। समाज में शर्मिंदगी के चलते अपने साथ हुई ठगी की जानकारी तक साझा नहीं करते हैं और न ही पुलिस में इसकी शिकायत करते हैं। यही वजह है कि सेक्सटार्शन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान के मेवात क्षेत्र, भरतपुर, हरियाणा और दिल्ली के दूरदराज क्षेत्रों में ऐसे कई गिरोह बैठे हुए हैं। ये गिरोह पुरुषों को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 2023 के बीच गुजरात में सेक्सटार्शन के मामलों में 85 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और कहीं न कहीं देश के बाकी राज्यों के हालात भी ऐसे ही हैं।

सेक्सटार्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेटा ने 'टेक इट डाउन' नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है, जो युवाओं को सेक्सटार्शन से बचाने में उनकी मदद करेगा। इसके जरिये व्यक्तिगत तस्वीरों को वायरल करने से रोकने में मदद मिलेगी। सेक्सटार्शन की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकारी स्तर पर भी व्यापक कदम उठाने चाहिए जिससे इस डिजिटल महामारी से समाज को सुरक्षित बनाया जा सके।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

कुंठित सोच से परे भारतीय संस्कृति

'सत्य और तथ्य सिद्ध है भारतीय संस्कृति' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में 'हृदयनारायण दीक्षित' ने उचित ही कहा है कि वैज्ञानिक विवेचन ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को सही सिद्ध किया है। पुरातत्व सर्वेक्षण में मिलने वाले अवशेष भारतीय संस्कृति के तथ्य और सत्य दोनों प्रकट करते हैं। फिर कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा इन तथ्यों पर सवाल उठाने का क्या औचित्य बनता है? भारत की समृद्ध संस्कृति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां पर पुरातात्विक खोदाई में समृद्ध नगर, कीमती आभूषण, सिक्के, लाक्षागृह जैसे प्राचीन अवशेष निकले हैं, पर ऐसा क्यों है कि भारत के बाहर किए गए पुरातत्व सर्वेक्षण में ऐसे समृद्ध और प्राचीन सभ्यता के अवशेष नहीं मिलते? विज्ञान हो या अध्यात्म, शिक्षा हो या जीवन जीने का ढंग, भारतीय संस्कृति हमेशा से ही हर क्षेत्र में आगे रही है। भारतीय संस्कृति में हमने महाभारत में चक्रव्यूह जैसी जटिल संरचना भी देखी है और रामायण में पत्थरों का जल में तैरना भी। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय देखे हैं और उन तथाकथित विदेशी विज्ञानियों से कई वर्षों पहले ही गुरुत्वाकर्षण, शून्य, बाइनरी डिजिट आदि का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट, भास्कराचार्य जैसे महान विद्वान भी। फिर हमारी संस्कृति काल्पनिक और पिछड़ी कैसे हो सकती है? जो बाबर, औरंगजेब, खिलजी आदि के रक्तरंजित इतिहास का समर्थन करते हैं उनके लिए ऐसी महान संस्कृति को समझ पाना कठिन है।

सोनल वर्मा, प्रयागराज

मेलबाक्स

बदलता विश्व और सीएए

'सीएए पर अमल' संपादकीय बदलते विश्व में सीएए को और अधिक बलवती करती है। भारत वसुधैव कुटुंबकम् के मूलमंत्र पर विश्वास करता है जिसका यह तात्पर्य कभी नहीं रहा कि देश में अनधिकृत रूप से कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। राष्ट्रहित में यह कानून समसामयिक है। किसी भी देश का नागरिक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भारत की नागरिकता ले सकता है। सीएए में कहीं ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि अमुक पंथ या आस्था से संबद्ध किसी अन्य देश का नागरिक भारत की नागरिकता नहीं ले सकता है। हां, कानूनी प्रक्रिया पूरी करना तो हमेशा से वांछित रहा है। ऐसे में विपक्ष का विरोध समझ से बाहर है। केवल वोट के लिए राष्ट्रहितों को तिलांजलि क्या उचित है। सीएए का दुष्प्रचार किसी भी स्तर पर सहन न किया जाए, जो इस कार्य में शामिल हों उनसे देश के कानून के अनुसार निपटा जाए। विभिन्न पंथों, आस्थाओं को मानने वालों, विभिन्न जातियों, संप्रदायों को भड़काने वालों के साथ अब सख्ती से निपटने का समय आ गया है। यह समय की मांग है कि राष्ट्रहित के सामने किसी भी निजी स्वार्थ को अपना मस्तक ऊंचा न करने दिया जाए। स्रोतों, संसाधनों, जनसंख्या विस्फोट, इंटरनेट मीडिया की बेरोकटोक बढ़ती प्रवृत्ति, आतंकवाद जैसी समस्याओं से जूझ रहे विश्व में भारत के हित में है सीएए।

योगराज, खरड़ (पंजाब)

हमारी सांस्कृतिक विरासत

हृदयनारायण दीक्षित द्वारा ''सत्य और तथ्य सिद्ध है भारतीय संस्कृति'' आलेख में जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं वे सच में सराहनीय हैं। हमारा इतिहास कहीं अधिक समृद्ध है, लेकिन इसे वामपंथियों ने तोड़ मरोड़ कर हमें बताया। हमें अपनी खोई विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए पुनर्जागरण करना होगा। इसकी चर्चाएं हर और आयोजित करनी होंगी। इसको सुधारने का भरसक प्रयास करना होगा। यह तभी संभव होगा जब हमारी शिक्षा नीति में बदलाव होगा। हमारे नीति निर्धारक जब इस पर खास ध्यान खास ध्यान देंगे। वामपंथियों ने हमारे इतिहास को बहुत क्षति पहुंचाई है। इसे सही और मूल रूप में जीवित करना अति आवश्यक है तभी हमारा समाज सही रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा। तभी हमारी युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति सजग होगी, जागृत होगी और इसे एक धरोहर के रूप में संचित रखने का प्रयास करेगी।

लाल बाबू, मुजफ्फरपुर, बिहार

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

63 प्रतिशत रहा बेंगलुरु में जाम का स्तर वर्ष 2023 में, जबकि पुणे में यह 57 प्रतिशत रहा। वहीं दिल्ली और मुंबई में यह स्तर क्रमशः 48 और 43 प्रतिशत रहा, विश्व के महानगरों में यातायात की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करने वाली एक वैश्विक संस्था (टामटाम) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार।

आजकल

महानगरों में बढ़ रही ट्रैफिक की समस्या

दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अनेक शहरों में रहने वाले लोग जब सड़क पर निकलते हैं तो उनमें से अधिकांश को यह महसूस होता है कि ट्रैफिक जाम की समस्या उनके ही शहरों में है। जबकि एक संबंधित रिपोर्ट में बताया गया है कि बेंगलुरु और पुणे में यह समस्या देश में सबसे अधिक है। वस्तुत: ये दोनों शहर इस मामले में विश्व के शीर्ष दस शहरों में शामिल हो चुके हैं। लिहाजा महानगरों में बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या का समग्र समाधान आवश्यक है

समीरा
शोधार्थी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

महानगरों में ट्रैफिक जाम की समस्या से बचाव के लिए अनूठे उपायों को अमल में लाना होगा। फाइल

विश्व के महानगरों में यातायात की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करने वाली एक वैश्विक संस्था (टामटाम) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में जिन दस महानगरों के यातायात को सबसे खराब माना है, उसमें भारत के दो बड़े शहर बेंगलुरु और पुणे भी शामिल हैं। वर्ष 2023 में बेंगलुरु में जाम का स्तर 63 प्रतिशत रहा, जबकि पुणे में 57 प्रतिशत रहा। वहीं दिल्ली और मुंबई में यह स्तर क्रमशः 48 और 43 प्रतिशत रहा। इन आकड़ों की चर्चा इसलिए है, क्योंकि यह निश्चित है कि जिस प्रकार बेंगलुरु और पुणे पिछले कुछ दशकों में शहरों से महानगरों में बदले हैं, उसी प्रकार आने वाले कुछ दशक में कई शहरों का आकार बढ़ेगा। भारत के ही अनेक शहर महानगरों में तब्दील होंगे और गांवों का देश माना जाने वाला भारत वर्ष 2050 तक शहरीकृत हो जाएगा। लेकिन यह शहरीकरण यदि चंडीगढ़ की तरह योजनाबद्ध तरीके से न होकर पुणे और बेंगलुरु की तरह बेतरतीब होगा तो देश की तस्वीर क्या रहेगी, वह इस रिपोर्ट से समझा जा सकता है।

वस्तुतः बेंगलुरु और पुणे हमारे देश में अपेक्षाकृत नए महानगर हैं। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस दौरान यहां लघु, मध्यम और भारी उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके लिए सरकारों ने नीतिगत तरीके से सहयोग भी दिया। इस कारण इन दोनों शहरों की आबादी बीते कुछ दशकों के दौरान तेजी से बढ़ी है। आदर्श स्थिति यह होती कि जिस प्रकार से उद्योगों को लेकर नीति बनाई गई, उसी प्रकार से सार्वजनिक परिवहन का ढांचा विस्तार करने और उसे सुविधाजनक बनाने की भी चिंता की जाती। परंतु यह दुर्भाग्य है कि यह चिंता सामान्य तौर पर समस्या के उत्पन्न होने के उपरांत की जाती है जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि इन शहरों के निवासियों की निर्भरता निजी वाहनों पर बढ़ती जाती है। अनेक महानगरों में 'कार कल्चर' पनपने का एक बड़ा कारण यह भी है। यह प्रवृत्ति पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में बढ़ रही है।

बहुत से लोग कार कल्चर को बढ़ती हुई संपन्नता से भी जोड़कर देखते हैं, परंतु ऐसा करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कहीं न कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खराब व्यवस्था ने लोगों को निजी वाहनों के उपयोग करने पर मजबूर किया है। किसी भी शहर में सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला सार्वजनिक वाहन बस है, जो अपेक्षाकृत कम किराये में अधिक लोगों को यात्रा करवाने में सक्षम है। लेकिन बसों का समय पर उपलब्ध न हो पाना, आसपास के सेटेलाइट शहरों तक पहुंच नहीं होना, पीक आवर्स के दौरान अत्यधिक भीड़ आदि कुछ कारण हैं जिससे अनेक लोग बस से यात्रा करने से बचते हैं। इसी प्रकार यदि मेट्रो ट्रेन की बात करें तो मेट्रो सेवाओं का फीडर नेटवर्क मजबूत न होने के कारण अनेक मेट्रो यात्रियों को परिवहन के विविध साधनों का उपयोग करते हुए मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना पड़ता है, लिहाजा वे असहजता महसूस करते हैं। ऐसे में इन यात्रियों की समस्याओं को समझा जाना चाहिए।

आज हम ऐसे समय में आ चुके हैं कि अधिकांश शहरों में निजी वाहन स्वामित्व ने जनसंख्या वृद्धि दर को पार कर लिया है और सड़कों एवं फ्लाईओवरों का अत्यधिक निर्माण कहीं न कहीं निजी वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ दिखते जा रहे हैं, जिस कारण ट्रैफिक पर काबू पाना मुश्किल दिखाई देता है। ऐसे में यदि हमें शहरों को जाम से मुक्त करना है तो न केवल सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना होगा, बल्कि 'कार कल्चर' से भी निपटना होगा। इस दृष्टि से देखें तो सिंगापुर का अनुभव हमारे लिए काफी काम का हो सकता है। जाम से निपटने के लिए वर्ष 1975 में सिंगापुर ने एरिया लाइसेंसिंग योजना शुरू की। इस योजना के तहत वाहन चालकों को पीक आवर्स में सोमवार से शनिवार तक प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना होता था। परिणामस्वरूप सिंगापुर में जाम का स्तर कुछ ही माह में 20 प्रतिशत तक गिर गया। सिंगापुर ने इस योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए वर्ष 1998 में इलेक्ट्रानिक रोड मूल्य निर्धारण योजना आरंभ की, जिसके अनुसार वाहन चालकों को स्थान, समय, वाहन के प्रकार के आधार पर शुल्क का भुगतान करना होता है। इससे प्रतिबंधित क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या कम हुई। इस शुल्क से जमा हुई राशि का उपयोग सिंगापुर सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में सुधार संबंधी कार्यों में इस्तेमाल किया।

शहरों से ट्रैफिक की समस्या को कम करना कोई अप्राप्य कार्य नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि उच्च गुणवत्ता वाले सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता, कुछ इलाकों में केवल सार्वजनिक वाहनों को ही चलने की इजाजत देना, साइकिल चलाने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना आदि नीतियां अपनाई जाएं। यदि शहरों में पर्यावरण अनुकूल और आरामदायक परिवहन विकल्प उपलब्ध कराया जाए, लोगों को समझाया जाए कि जाम मुक्त, हरित और स्मार्ट सिटी बनाने की जिम्मेदारी सरकार और नागरिक परस्पर तौर पर साझा करें, तो हमारे शहरों की स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है।

टामटाम इंडेक्स : टामटाम एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के एम्सटर्डम में है। वर्ष 2011 से यह लगभग प्रतिवर्ष ट्रैफिक सूचकांक जारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को ट्रैफिक से जुड़ी सूचनाएं मुहैया कराना है, ताकि लोग कब और कैसे यात्रा करें, इसके बारे में बेहतर विकल्प चुन सकें। यह ट्रैफिक इंडेक्स शहरी योजनाकारों, नीति निर्माताओं और वाहन चालकों के लिए एक व्यापक उपकरण बन गया है, क्योंकि यह यातायात से हुए जाम को समझने और उनके नियंत्रण के लिए नीति निर्माण में मदद करता है। यह रिपोर्ट परिवहन के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर जाम के प्रभाव के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जैसे कब और कहां कितना यातायात कितना धीमा रहा। इस साल की रिपोर्ट में टामटाम ने 55 देशों के 387 शहरों में किस प्रकार जाम ने यात्रा के औसत समय, ईंधन लागत और कार्बन उत्सर्जन को प्रभावित किया, इस संबंध में जानकारी दी है।

कैब किराया निर्धारण में विसंगतियों से मुक्ति

चिन्मय कुमार भट्ट
अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में न्यूनतम कैब किराया निर्धारण का निर्णय लिया है। गिग कार्य और प्लेटफार्म कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के संदर्भ में भारत में लिए गए संभवतः यह अब तक के बड़े निर्णयों में से है। वैसे तो शहरों में आवागमन और यात्री भाड़ा को लेकर सरकारें निर्णय करती रही हैं और किराये के वाहनों के बाजार को भी देखें तो स्वयं कर्नाटक में इस तरह का निर्णय कोई पहली बार नहीं लिया गया है। वर्ष 2021 में भी सरकार ने किराया निर्धारण में हस्तक्षेप किया था, लेकिन तब मुक्त बाजार के सिद्धांत और तकनीक के प्रयोग की युति पर स्थापित प्लेटफार्म इस क्षेत्र में आज की तरह हावी नहीं थे। राज्य सरकार द्वारा घोषित नई किराया संरचना के अनुसार, टैक्सी वाहनों को वाहन की लागत के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। इस वर्गीकरण के अनुसार प्रथम श्रेणी में 10 लाख रुपये तक की लागत वाले वाहन आते हैं जिनके लिए चार किमी तक का मूल किराया सौ रुपये और प्रति अतिरिक्त किमी 24 रुपये तय किया गया है। दूसरी श्रेणी में 10 से 15 लाख वाले वाहन आते हैं जिनके लिए आरंभिक चार किमी के लिए मूल किराया 115 रुपये होगा और उसके बाद प्रति किमी की लागत 28 रुपये होगी।

इसके अलावा कैब कंपनियों को यात्रियों से सर्ज प्राइसिंग (मांग अधिक होने के कारण किराया सामान्य से अधिक दर से निर्धारित किए जाने की नीति) वसूलने की अनुमति नहीं होगी। वस्तुतः सर्ज प्राइसिंग को लेकर पहले भी चर्चा होती रही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कैब आपरेटरों को उनके द्वारा सर्ज प्राइसिंग की गणना करने के तरीके में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, इसके बावजूद यात्रियों को अक्सर कैब कंपनियों द्वारा सर्ज प्राइसिंग की गणना करने के अपारदर्शी तरीके से परेशानी होती रही है। विशेष रूप से जब इस कारण यात्रियों को कैब बुक करते समय बताई गई राशि से कहीं अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है। लिहाजा सर्ज प्राइसिंग आजकल एक आम समस्या बन चुकी है, परंतु उपभोक्ताओं के पास इससे बचने का कोई ठोस उपाय दिख नहीं रहा है। पिछले एक-डेढ़ दशक में आसानी से उपलब्ध पूंजी की शक्ति से कई टैक्सी कंपनियों ने लोगों को सस्ते किराये पर टैक्सी उपलब्ध कराते हुए इस सेगमेंट में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है। इस कारण आज कुछ चुनिंदा कंपनियां इस स्थिति में आ चुकी हैं कि किसी भी समय और रूट पर किराये में अपारदर्शी तरीके से वृद्धि या कमी कर सकती हैं।

कर्नाटक सरकार के उपरोक्त निर्णय के लागू होने से इन कंपनियों की सर्ज प्राइसिंग की ताकत कम होगी। उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सकता है। चालकों को इस नियम से न्यूनतम किराये के निर्धारण से भी लाभ होगा, परंतु यह निर्णय उपभोक्ताओं और चालकों से कहीं अधिक प्लेटफार्म आधारित इस प्रकार के समूचे अर्थतंत्र पर पड़ सकता है। केवल दूरी को आधार बना कर किराये के निर्धारण से अपनी व्यावसायिक संरचना और तरीके के कारण कुछ कंपनियां ज्यादा तो कुछ कम प्रभावित होंगी, जिस कारण कैब की उपलब्ध पर तो फर्क पड़ेगा ही, भविष्य में इस बाजार में नए समीकरण भी सामने आ सकते हैं।

खरी-खरी

वैलेंटाइन के खर्चे

रेखा शाह आरबी

बसंत ऋतु, मधुमास, ऋतुराज आदि नामों से पुकारा जाने वाला प्रेमियों का प्रतीक्षातीत समय फरवरी अपने पूरे लाव लश्कर के संग आजकल आपके साथ है। दुनिया में चाहे जितना हाहाकार मचा रहे, परंतु प्रेम के पंछी प्रेम के गीत गाने से कहां चूक सकते हैं। जिन्हें प्रेम करना है, वे प्रेम करके ही मानते हैं।

पहले के जमाने में तो इसकी राह में हजार अड़चनें रहती थीं। पर अब स्मार्टफोन और इंटरनेट मीडिया ने बहुत कुछ आसान कर दिया है। आजकल तो इसके भी ट्रेंड चलते हैं। वीक चलते हैं। आजकल इंटरनेट मीडिया का जमाना है। हर कोई इस मीडिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चाचा, चाचियों के साथ तो भैया, भाभियों के साथ और मामा, मामियों के साथ जुड़े हुए हैं। यह अलग बात है कि वह किसी अलग के चाचा हैं और वह किसी अलग की चाची हैं। जब इतने सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो बैचलर क्यों पीछे रहें, वे भी कन्याओं के साथ अटैच हैं।

इधर दिल में खयाल आया, उधर उसे पहुंचा दिया गया। अब कबूतर और चिट्ठी वाला जमाना तो रहा नहीं कि महीनों इंतजार किया जाए। बस किसी पर दिल आया और तुरंत खयाल जाहिर कर दिया। हां है तो ठीक है, नहीं तो अगले स्टेशन के तरफ बंदा बढ़ जाता है। आजकल वह जमाना नहीं रहा कि हीर रांझा वाली बेवकूफी की जाए और लैला मजनूं की तरह पत्थर खाया जाए।

इंटरनेट मीडिया के सहयोग से दिल मिल ही जाता है। झपटू जी भी इस महीने की प्रतीक्षा पूरे वर्ष करते हैं। झपटू जी डिजिटल और रियल दोनों ही तरह की डेटिंग करते हैं। इसमें खर्चा भी होता है। पिछली बार तो डेटिंग का खर्चा घर का अनाज बेचकर निकाल लिया था। इस बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि पिछली बार उनके पिताजी को शक हो गया था। वैसे झपटू जी ने सरकार के पास आवेदन भेजा है वैलेंटाइन डे का भत्ता देने के लिए। देखना है कि सरकार कब तक उनकी अर्जी मंजूर करती है, ताकि उनका वैलेंटाइन डे सही सलामत निकल जाए। वैसे दूसरे आप्शन के तौर पर उन्होंने इस बार भूसा बेचने का प्लान बनाया है। अगर सफल रहा तो वैलेंटाइन डे अच्छे से मन जाएगा।

X पोस्ट

खामोशी से काम करती भारतीय कूटनीति ने बताया कि कहीं किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। कतर ने आठ भारतीयों को रिहा कर दिया। सात भारत लौट आए हैं।
श्वेता सिंह@SwetaSinghAT

बिहार में एक खेला ऐसा भी हुआ। राजद विधायक चेतन आनंद एक दिन पहले तक तेजस्वी यादव के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने विश्वासमत पर जदयू के समर्थन में मतदान किया।
अमन शर्मा@AmanKayamHai_

क्रिकेट मैच की तरह राजनीति में भी कब किसे और कहां उपयोग करना है, बहुत मायने रखता है। राज्यसभा के लिए चयन में भाजपा ने इसे साबित किया है। सूत्रों को भी इसकी कोई भनक नहीं लगी। आरपीएन का नाम होना और कवि-कथावाचक कुमार विश्वास का नाम नदारद होना इसका प्रमाण है।
राजेश शुक्ला@astroraj

लगातार आंदोलनों के कारण पंजाब में निवेश 85 प्रतिशत गिर गया है। प्रति व्यक्ति आय में कभी शीर्ष पर रहा पंजाब आज 16वें स्थान पर है। कृषि में मध्य प्रदेश जैसा राज्य पंजाब से आगे निकल गया तो खेलों में हरियाणा। पंजाब के लोगों को गंभीरता से विचार करना होगा कि वे कहां जा रहे हैं।
अशोक श्रीवास्तव@AshokShrivasta6

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या प्रमुख दलों की राष्ट्रीय सरकार पाकिस्तान का भला कर सकती है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का मूल कारण गांधी परिवार की रीति-नीति है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

लौटे मुंह से मौत के पड़ी जान में जान,
जो लौटे वे कर रहे मोदी का गुणगान।
मोदी का गुणगान उन्हीं को रास न आए,
जिनके शासनकाल गए हम सब धकियाए।
देश रहा पहचान रहे जो सिक्के खोटे,
स्वागत उनका आज कतर से जो हैं लौटे।
- ओमप्रकाश तिवारी

संदेशखाली की अशांति दे रही बड़ा संदेश

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल डायरी

बांग्लादेश की सीमा से सटे उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में पिछले कई दिनों से जिस तरह की अशांति व्याप्त है, उसके निहितार्थ को समझने की जरूरत है। संदेशखाली की इस अशांति में बड़ा संदेश छिपा है। राशन घोटाले व ईडी की टीम पर हमले में वांछित तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय बाहुबली नेता शाहजहां शेख पर जैसे ही कार्रवाई की उम्मीद जगी तो उसकी प्रतिक्रिया संदेशखाली के घरों से निकलकर गलियों व सड़कों पर अभिव्यक्त होने लगी, इसे ममता सरकार और तृणमूल नेतृत्व को किसी उकसावे के तहत फौरी या आकस्मिक प्रतिक्रिया समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। तृणमूल नेताओं के खिलाफ यह आक्रोश क्यों है, इसका गंभीरता से आकलन करना होगा। संदेशखाली में शाहजहां शेख, शिबप्रसाद हाजरा उर्फ शिबू हाजरा और उत्तम सरदार जैसे तृणमूल नेताओं के खिलाफ जिस तरह के प्रदर्शन, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं, वह विपक्षी नेताओं के उकसावे की वजह से है, ऐसा नहीं लग रहा। जिस तेवर के साथ महिलाएं झाड़ू, लाठी, राड और अन्य धारदार हथियार लेकर सड़कों पर निकलीं और उन नेताओं की शराब दुकान में तोड़फोड़ से लेकर जमीन कब्जा कर बनाए गए पोल्ट्री फार्म और गार्डेन हाउस में आग लगा दी, उसे स्वतः स्फूर्त माना जा रहा है।

विरोध-प्रदर्शन करने वालों की एक ही मांग है- शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार की गिरफ्तारी। बुधवार को जब इस विरोध-प्रदर्शन की शुरुआत हुई तो आरोप लगा कि उसके बाद उपरोक्त तीनों के समर्थकों ने गांव में घुसकर महिलाओं को मारा-पीटा। उसके बाद फिर से महिलाएं सड़क पर उतर आईं। स्थिति को बेकाबू होता देख जिला प्रशासन को इलाके में धारा 144 लागू करने के साथ ही इंटरनेट सेवा तक बंद करनी पड़ी। उधर लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए तृणमूल नेतृत्व को अपने नेता उत्तम सरदार को पार्टी से छह साल के लिए निलंबित करना पड़ा। इसके बाद शनिवार रात को पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं ईडी टीम पर हमले का मास्टरमाइंड शाहजहां 39 दिनों बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। विरोध-प्रदर्शन के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने भाजपा के एक नेता विकास सिंह और संदेशखाली के पूर्व माकपा विधायक निरापद सरदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रशासन ने भाजपा और माकपा नेता को गिरफ्तार कर यह बताने की कोशिश की है कि संदेशखाली की घटना सुनियोजित है।

संदेशखाली में तृणमूल नेता की गिरफ्तारी के लिए विरोध प्रदर्शन करतीं महिलाएं। फाइल

भाजपा ने संदेशखाली में अशांति का मुद्दा विधानसभा में उठाते हुए शनिवार को राजभवन तक मार्च निकाला तो सोमवार को विधानसभा में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद शनिवार को ही राज्यपाल ने राज्य सरकार से अशांति को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल द्वारा क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कोई पहल नहीं करने पर सोमवार को धारा 144 का उल्लंघन कर पार्टी के 67 विधायकों के साथ संदेशखाली जाने के लिए निकला तो मौके से 50 किमी दूर कोलकाता में ही उन्हें रोक दिया गया। उधर राज्यपाल बोस संदेशखाली पहुंचे तो सड़क पर बैठकर महिलाओं ने अपनी पीड़ा सुनाई। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपित नेताओं को सत्तारूढ़ दल द्वारा बचाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस पर आरोपित नेताओं और उसके समर्थकों के साथ मिलीभगत एवं स्थानीय आम लोगों के खिलाफ ही अनावश्यक कार्रवाई करने का आरोप लगाया है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शाहजहां और उसके सहयोगी स्थानीय लोगों की जमीन हड़पने के साथ-साथ उन्हें उनके द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायों में बेगारी करने के लिए मजबूर व अत्याचार करते थे। यह भी आरोप है कि संदेशखाली में महिलाएं भगोड़े नेता और उसके सहयोगियों के हाथों अपमान और छेड़छाड़ के भय से सूरज ढलने के बाद अपने घरों से बाहर निकलने से डरती थीं। कहा यह भी जा रहा है कि शाहजहां और उसके साथी शिबू और उत्तम ने संदेशखाली में आतंक और गलत धंधे का पूरा साम्राज्य फैला रखा है। उनके पास कई हजार बीघा जमीन पर फैला मछली पालन केंद्र (बांग्ला में भेड़ी) है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके के 90 प्रतिशत भेड़ी पर इन्हीं लोगों का कब्जा है। वर्ष 2011 से पूर्व इसी तरह से माकपा नेताओं पर आरोप लगते थे। इसी क्षेत्र से महज कुछ दूर स्थित इलाके में 2011 से पहले माजिद मास्टर नामक माकपा नेता का राज चलता था। वाम शासनकाल में इस क्षेत्र के भेड़ी इलाके में उसकी तूती बोलती थी और वह आतंक का पर्याय था। किसी की उसके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी, परंतु जब लोगों को लगा कि अब कार्रवाई हो सकती है तो इसी तरह लोगों का आक्रोश फूट पड़ा था। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के निताई में 2009 में एक नरसंहार हुआ था। आरोप है कि माकपा नेता रथिन दंडपत से पीड़ित लोग उसके खिलाफ मुखर हुए थे तो उसके घर की छत से गोलियां चली थीं, जिसमें नौ ग्रामीणों की मौत हुई थी।

अब आतंक फैलाने के आरोप तृणमूल नेताओं पर लग रहे हैं। माकपा शीर्ष नेतृत्व उस समय अपने नेताओं के खिलाफ पनपे आक्रोश को नहीं समझ सका था, जिसका नतीजा वर्ष 2011 में सामने आया था। सत्ता में आने के 13 वर्षों बाद अब शाहजहां-शिबू जैसे तृणमूल नेताओं के खिलाफ भी ऐसा ही आक्रोश प्रस्फुटित हो रहा है। यह बड़ा संदेश और संकेत है।

मंथन

मनोरंजन उद्योग में पायरेसी

पायरेसी फिल्म उद्योग की एक बड़ी समस्या है। इस कारण इस उद्योग को हर साल 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। लिहाजा इस संदर्भ में कुछ नए प्रविधान किए जा रहे हैं

मुकुल श्रीवास्तव
प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय

समूचे विश्व में पायरेसी एक बड़ी समस्या है। इंटरनेट ने इसे और जटिल बना दिया है। साफ्टवेयर पायरेसी से शुरू हुआ यह सफर फिल्म, संगीत, धारावाहिकों आदि तक पहुंच गया है। मोटे तौर पर पायरेसी से तात्पर्य किसी भी साफ्टवेयर, संगीत, फिल्म आदि के पुनरुत्पाद से है। जिसमें मौलिक रूप से इन्हें बनाने वाले को कोई आर्थिक लाभ नहीं होता और पायरेसी से पैदा आय इस गैर कानूनी कार्य में लिप्त लोगों में बंट जाती है। इंटरनेट से पहले यह काम ज्यादा श्रमसाध्य था व इसकी गति धीमी थी, परंतु इंटरनेट ने पायरेसी के वितरण में तेजी ला दी है, जिससे लाभ बढ़ा है।

भारत जैसे देश में जहां इंटरनेट बहुत तेजी से फैल रहा है, आनलाइन पायरेसी का कारोबार भी अपना रूप बदल रहा है। पहले इंटरनेट स्पीड कम होने की वजह से ज्यादातर पायरेसी टोरेंट से होती थी, परंतु भारत समेत सारी दुनिया में पायरेसी का चरित्र बदल रहा है, क्योंकि अब हाई स्पीड इंटरनेट स्मार्टफोन के जरिये हर हाथ में पहुंच रहा है, तो लोग पायरेटेड कंटेंट को सेव करने के बजाय सीधे इंटरनेट स्ट्रीमिंग सुविधा से देख रहे हैं। आनलाइन पायरेसी में मूलतः दो चीजें शामिल हैं- साफ्टवेयर और आडियो-वीडियो कंटेंट, जिनमें फिल्में, गीत-संगीत आदि शामिल हैं। एक तो साफ्टवेयर की लोगों को रोज जरूरत होती नहीं, फिर अनेक साफ्टवेयर आनलाइन मुफ्त उपलब्ध हैं या काफी सस्ते हैं। आज जब सारा मनोरंजन फोन में सिमट आया है और इन कार्यों के लिए कुछ वेबसाइट तमाम कंटेंट उपभोक्ताओं को मुफ्त में उपलब्ध कराती हैं व अपनी वेबसाइट पर आने वाले ट्रैफिक से विज्ञापनों से कमाई करती हैं, पर उपभोक्ताओं को वे जो कंटेंट उपलब्ध करा रही हैं, वे उनके बनाए नहीं होते हैं। साथ ही वेबसाइटें जो लाभ उससे कमा रही होती हैं, उसका हिस्सा भी मूल कंटेंट निर्माताओं को नहीं मिल पाता है।

मनोरंजन उद्योग में आनलाइन चोरी पर नजर रखने वाली एक वेबसाइट 'मुसो' के अनुसार पायरेसी के लिए जिस तकनीक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसमें स्ट्रीमिंग पहले नंबर पर है। मुसो कापीराइट उल्लंघनों पर आंकड़ा एकत्र करती है। इंटरनेट पर ऐसी कई साइट्स हैं, जहां से पायरेटेड कंटेंट मिल जाती हैं। जैसे ही इन्हें ब्लाक किया जाता है, ये यूआरएल बदलकर फिर से काम करने लगती हैं।

वस्तुतः पायरेसी फिल्म उद्योग की बड़ी समस्या है। वैश्विक सलाहकार फर्म 'अंकुरा' की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में टोरेंट साइटों के माध्यम से सात अरब से अधिक विजिट के साथ कंटेंट पायरेसी वेबसाइटों पर जाने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत से आगे अमेरिका और रूस जैसे देश हैं। संगीत, फिल्मों, साफ्टवेयर और किताबों की पायरेसी में वाट्सअप व टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग एप ने इसे और गंभीर बना दिया है, जो टोरेंट साइट्स या एग्रीगेटर एप्स के बारे में जानकारी प्रसारित करते हैं, जहां पायरेटेड सामग्री उपलब्ध हैं। पायरेसी वेबसाइटों पर आने वाले ट्रैफिक में टीवी सामग्री का हिस्सा 46.6 प्रतिशत था, इसके बाद प्रकाशन सामग्री (किताबों) का योगदान 27.8 प्रतिशत रहा। फिल्म पायरेसी 12.4 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इसके बाद संगीत व साफ्टवेयर का स्थान आता है, जो क्रमशः सात और 6.2 प्रतिशत है।

भारत में वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म पायरेसी के कारण कुल राजस्व का 25-30 प्रतिशत हिस्सा गंवा रहे हैं।

कुल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा मूल कंटेंट निर्माताओं को पायरेसी के कारण गंवाना पड़ता है। प्रतीकात्मक

सरकार ने इसके लिए सिनेमैटोग्राफ संशोधन बिल 2023 में कुछ नए प्रविधान जोड़े हैं। इस विधेयक का उद्देश्य 'पायरेसी' की समस्या पर व्यापक रूप से अंकुश लगाना है। इस बिल के तहत फिल्म की पायरेसी करने वालों को तीन माह से लेकर तीन साल की जेल हो सकती है। साथ ही फिल्म की निर्माण लागत का पांच प्रतिशत जुर्माना भी भरना होगा। फिल्म को गैरकानूनी तरीके से दिखाना या फिर इसकी गैर कानूनी रिकार्डिंग भी अपराध की श्रेणी में आएगी। निजी उपयोग, करेंट अफेयर्स, रिपोर्टिंग और फिल्म क्रिटिसिज्म के लिए कापीराइट कंटेंट उपयोग किया जा सकेगा।

नई प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर पायरेसी व्यापक हो गई है, लिहाजा कई कानून अब आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। कापीराइट अधिनियम, 1957 जैसे कानूनों में कई समस्याएं हैं और वे कठोर नहीं हैं, जिससे अपराधियों को दंडित करना कठिन होता है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आइपीआर) नीति 2016 सहित नए कानूनों का पालन और डिजिटल अपराध इकाइयों की स्थापना प्रारंभिक चरण में है। पर्याप्त कानूनों के अभाव में, अदालतें पायरेसी के मामले में कुछ खास नहीं कर पाती हैं। अब देखना यह है कि सिनेमैटोग्राफ संशोधन बिल 2023 पायरेसी की समस्या को कितना कम कर पाएगा।

****